page 1 and 8 June 10_page 1 Mar 25 final ds.qxd 10-Jun-26 12:50 AM Page 1

मौसम जम्मू — न्यूनतम 28, अधिकतम 42

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

देहात संदेश

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-141 | जम्मू तवी, बुधवार 10 जून, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग के निर्माण को भारत के अवसंरचना इतिहास का 'स्वर्ण अध्याय' बताया

गांदरबल, 09 जून। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को जोजिला सुरंग के निर्माण को भारत के अवसंरचना इतिहास का स्वर्ण अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह सुरंग हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करके लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के लिए जीवन रेखा का काम करेगी। समारोह के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गडकरी ने कहा कि 14 किलोमीटर लंबी यह सुरंग देश की सबसे महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है, जिसे चुनौतीपूर्ण भूभाग और खराब मौसम के बावजूद वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाया गया है। उन्होंने परियोजना में शामिल इंजीनियरों, श्रमिकों और एजेंसियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि निर्माण कार्य लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर शून्य से नीचे के तापमान में किया गया, जिसमें लगभग 80 फीसदी स्थानीय श्रमिक थे। उन्होंने कहा कि यह सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करके सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार, आर्थिक गतिविधि और रणनीतिक आवागमन को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्री ने लद्दाख के लिए कई नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला लेह साउथ बाईपास (48 किमी) और 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला लेह नॉर्थ बाईपास (7.6 किमी) शामिल हैं। इनका उद्देश्य यातायात जाम को कम कर । और संपर्क को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि 2.6 किमी लंबी फातु ला ट्विन-ट्यूब सुरंग पर काम तीन महीने के भीतर शुरू हो जाएगा, जबकि 3,500 करोड़ रुपये की लागत वाली टेला पास सुरंग परियोजना अंतिम डीपीआर चरण में है और अगले साल मार्च से पहले इसके ठेके दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा गडकरी ने श्रीनगर-गुमरी सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन की घोषणा की, जिससे संपर्क और मजबूत होगा और जोजिला सुरंग का पूरक बनेगा। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार और दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों तक साल भर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराया।

जोजिला सुरंग की अंतिम चट्टान की खुदाई का गडकरी ने शुभारंभ किया

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को जोजिला सुरंग की अंतिम चट्टान की खुदाई का शुभारंभ किया। यह उपलब्धि 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पूरा होने पर यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सड़क सुरंग होगी। इस परियोजना से कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित होने के साथ-साथ क्षेत्र में परिवहन, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक ये बड़ी कामयाबी तय समय से 6 महीने पहले ही हासिल कर ली गई है। इस सुरंग का निर्माण हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 11,578 फीट की ऊंचाई पर कर रही है। 13.15 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का 13 किलोमीटर से अधिक हिस्सा पूरा हो चुका है, जिससे यह सुरंग निर्माण के उस महत्वपूर्ण पड़ाव के करीब पहुंच गई है जहां दोनों सिरों से खुदाई के सिरे मिलते हैं।

जोजिला सुरंग में ऐतिहासिक सफलता पर उमर ने किया स्वागत, गडकरी से कारगिल के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने की अपील

मिनीमार्ग (लद्दाख), 9 जून। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से अपने प्रभाव का उपयोग कर कारगिल के लिए नियमित और सीधी हवाई सेवा शुरू कराने की अपील की।

यह अपील उन्होंने यहां आयोजित जोजिला सुरंग के ब्रेकथ्रू समारोह को संबोधित करते हुए की। उन्होंने लद्दाख के लोगों को हर मौसम में संपर्क सुविधा के सपने के साकार होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के लिए बधाई दी।

उमर अब्दुल्ला ने कहा,मैं लद्दाख के लोगों को बधाई देता हूं और गडकरी जी तथा उनके मंत्रालय के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। यह उपलब्धि हमें हर मौसम में निर्बाध संपर्क के सपने के और करीब ले जाएगी।

हालांकि उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों का एक सपना पूरा होने के करीब है, लेकिन कारगिल के लिए नियमित और सीधी हवाई सेवा का सपना अभी भी अधूरा है।

उन्होंने कहा,एक और सपना पूरा होना बाकी है, वह है कारगिल के लिए नियमित और सीधी हवाई सेवा। मैंने भी इसके लिए प्रयास किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। यह कारगिल के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है।

गडकरी से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा,

आप एक गतिशील और कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रभाव का उपयोग कर इस आकांक्षा को भी पूरा कराने में मदद करें। बेहतर हवाई और सड़क संपर्क से इस क्षेत्र को बहुत लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना का सपना कई लोगों ने देखा था, लेकिन उसे साकार नहीं कर पाए थे।

मंगलवार को जोजिला सुरंग परियोजना ने अपनी पूर्णता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब हिमालय को चीरती इस उच्च ऊंचाई वाली परियोजना में अंतिम 2.5 मीटर हिस्से को विस्फोट के माध्यम से जोड़ा गया।

गडकरी ने लद्दाख के मिनीमार्ग स्थित सुरंग के पूर्वी छोर के पास रिमोट बटन दबाकर ब्रेकथ्रू स्थल पर विस्फोट किया। इस अवसर पर उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे।

अधिकारियों के अनुसार, इस उपलब्धि के साथ दुनिया की सबसे लंबी एकल-ट्यूब द्वि-दिशीय सुरंग के दोनों छोर आपस में जुड़ गए हैं। यह सुरंग जोजिला दर्रे को पार करने में लगने वाले लगभग डेढ़ घंटे के समय को घटाकर मात्र 15 मिनट कर देगी।

इस सफल ब्रेकथ्रू के साथ कश्मीर और लद्दाख के बीच पूरे वर्ष संपर्क बनाए रखने का लंबे समय से देखा जा रहा सपना साकार होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा,

दशकों तक इस क्षेत्र के लोगों को सर्दियों में जोजिला दर्रा बंद होने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यह सुरंग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और वाणिज्य तक आसान पहुंच उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी।

उन्होंने उम्मीद जताई कि परियोजना का शेष कार्य भी जल्द पूरा किया जाएगा ताकि सुरंग को शीघ्र पूरी तरह से संचालन के लिए खोल दिया जा सके।

खबर संक्षेप

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने एसीबी चालानों की मैनुअल स्वीकृति की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), जम्मू-कश्मीर द्वारा दायर किए जाने वाले चालानों की मैनुअल स्वीकृति की व्यवस्था को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह विस्तार 23 अप्रैल 2026 को जारी उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश संख्या 608/2026/आरजी/जीएस के क्रम में दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि एसीबी चालानों की मैनुअल स्वीकृति पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत जारी रहेगी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई 2026 के बाद इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चालान प्रस्तुत करने में आ रही सभी तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जाए। रजिस्ट्रार जनरल एम. के. शर्माद्वारा जारी इस आदेश की प्रतियां न्यायिक अधिकारियों, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अपराध शाखा तथा अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई और जानकारी के लिए भेजी गई हैं। यह निर्णय ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने तथा अंतरिम अवधि के दौरान एसीबी मामलों की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने देने के उद्देश्य से लिया गया है।

असगर हुसैन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त

जम्मू , 9 जून । जम्मू-कश्मीर सरकार ने असगर हुसैन (जेकेएएस) को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के विशेष सचिव के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार हुसैन जो पहले समायोजन के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे को प्रशासन के हित में इस महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है।

भारत में परिसर खोलेंगे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के तीन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 09 जून । केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तीन प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और यूजीसी अध्यक्ष डॉ. विनीत जोशी ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को स्वीकृति पत्र (एलओपी) सौंपे।

पीएम मोदी के नेतृत्व में कश्मीर शांति, स्थिरता और विकास के नए दौर का साक्षी : रक्षा राज्य मंत्री

श्रीनगर, 9 जून। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर शांति, स्थिरता और विकास के नए युग का अनुभव कर रहा है। उन्होंने बढ़ती पर्यटक संख्या और जम्मू-कश्मीर में फिल्म निर्माण गतिविधियों के पुनर्जीवन को इसका प्रमाण बताया। पुलवामा जिले में एम्स अवंतीपोरा परियोजना की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा,पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर में 2.41 करोड़ पर्यटक आए थे, जबकि इस वर्ष अब तक 1.77 करोड़ पर्यटक यहां आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले अधिकांश फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी, लेकिन 1980 के दशक के अंत में अशांति के कारण यह संख्या घट गई थी। अब स्थिति बदल चुकी है। पिछले वर्ष घाटी में 400 फिल्मों की शूटिंग हुई, उन्होंने कहा। सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने पर जोर देते हैं हमारा भारत एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उन्होंने कहा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वह 1970 के दशक से नियमित रूप से कश्मीर आते रहे हैं। उन्होंने कहा,उस समय के कश्मीर और आज के कश्मीर में बहुत बड़ा अंतर है। यहां व्यापक विकास हुआ है और पिछले 12 वर्षों में हुए विकास की तुलना किसी अन्य दौर से नहीं की जा सकती। सेठ ने कहा कि हाल के वर्षों में कश्मीर का क्रिकेट बैट उद्योग भी काफी विकसित हुआ है। भारत ने कश्मीर से बने लगभग 30 लाख क्रिकेट बैट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी रब जैसे देशों को निर्यात किए हैं। एम्स अवंतीपोरा परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर के लोगों को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा,अब लोगों को इलाज के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा।

पीओजेके में हिंसा के बाद भारत ने पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपील

नई दिल्ली, 9 जून। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को उसके कथित मानवाधिकार उल्लंघनों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब रिपोर्टों के अनुसार पीओजेके के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के दौरान 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि इस्लामाबाद अपनी विफलताओं को छिपाने और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, हम इस संदर्भ में पाकिस्तान से फैलाए जा रहे फर्जी समाचारों और वीडियो का एक पैटर्न लगातार देख रहे हैं। यह पाकिस्तान की अपनी विफलताओं को छिपाने और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान हटाने की एक हताश कोशिश है।

चेनानी-नाशरी मार्ग पर नई दो-ट्यूब सुरंग को मंजूरी, सोमवती अमावस्या पर जम्मू-हरिद्वार विशेष ट्रेन भी चलेगी

जम्मू, 9 जून। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंहने मंगलवार को घोषणा की कि उधमपुर को रामबन जिले से जोड़ने वाले चेनानी-नाशरी खंड पर मौजूदा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंगके समानांतर एक नई दो-लेन ट्यूब सुरंग के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

इस विकास को उधमपुर के लिए एक और अच्छी खबर बताते हुए उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरीका आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। डॉ. सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी मांग स्वीकार करते हुए जम्मू-कश्मीर में एनएच-44 पर चेनानी-नाशरी मार्ग स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के समानांतर नई दो-लेन ट्यूब सुरंग के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर किया। इससे इस मार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव में कमी आएगी और यात्रा अधिक सुगम होगी।卐

उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने 2 अप्रैल 2017 को इस सुरंग का उद्घाटन किया था।

पूर्व में चेनानी-नाशरी सुरंग के नाम से जानी जाने वाली 9.28 किलोमीटर लंबी यह जुड़वां ट्यूब ऑल-वेदर सुरंग एनएच-44 पर स्थित है और लगभग 1,200 मीटर की ऊंचाई पर निचले हिमालयी क्षेत्र से होकर गुजरती है।

मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर में लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण का आह्वान किया

श्रीनगर, 9 जून। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें संबंधित प्रशासनिक सचिवों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के कार्यान्वयन और संतृप्तिकरण की समीक्षा करना था। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जोर दिया कि इन कल्याणकारी योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थियों तक पूर्ण संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए लोगों तक सक्रिय रूप से पहुंच बनाकर और विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए व्यापक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता बताई गई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्यों और विभिन्न योजनाओं के तहत पहले से कवर किए गए लाभार्थियों के बीच की खाई को पाटा जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से हर इच्छित लाभार्थी तक पहुंचे। ग्रामीण स्तर पर पहुंच के महत्व पर जोर देते हुए डुल्लू ने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों और परिवारों की पहचान और नामांकन के लिए ठोस कार्ययोजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर पात्र लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित रखना जनता के साथ अन्याय होगा। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि विभाग अपनी-अपनी योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करें और हर प्रशासनिक स्तर पर मापनीय लक्ष्य निर्धारित करें, ताकि योजनाओं का लाभ व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। इससे पहले, योजना विकास और निगरानी विभाग की आयुक्त सचिव आर. एलिस वाज ने बैठक को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में कुल 66 लाभार्थी-उन्मुख योजनाएं 18 विभागों के माध्यम से लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं लोगों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं और उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विस्तृत प्रस्तुति देते हुए आयुक्त सचिव ने प्रत्येक योजना के तहत लक्षित लाभार्थी समूहों और नकद हस्तांतरण, खाद्य सुरक्षा, आवास सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक सहायता तथा आजीविका संवर्धन जैसी सहायता के स्वरूप को विस्तार से बताया। बैठक में बताया गया कि 66 योजनाओं में से 21 सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा, 8 स्वास्थ्य विभाग द्वारा, 7-7 कृषि उत्पादन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, 3 जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा तथा शेष योजनाएं अन्य विभागों द्वारा लागू की जा रही हैं।

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर बहु-वाहन दुर्घटना में बीएसएफ के दो जवान घायल

रामबन/जम्मू, 9 जून। अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के लिए तैनाती पर जा रहे सुरक्षा कर्मियों से भरी एक बस के दो अन्य वाहनों से टकरा जाने के कारण मंगलवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई दुर्घटना में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

इस बीच, दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू से अनंतनाग जा रही बीएसएफ कर्मियों की बस, जो अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के लिए रवाना हुई थी, रामबन जिले के पीराह क्षेत्र में पहले एक यात्री वाहन **मारुति अर्टिगासे टकराई और उसके बाद एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा भिड़ी।

दुर्घटना में सहायक उपनिरीक्षक **संजीत कुमारऔर हेड कांस्टेबल **अरवीन कुमारको मामूली चोटें आईं। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रामबन पहुंचाया गया।

अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और सड़क का संबंधित हिस्सा आंशिक रूप से अवरुद्ध हो गया था।

बाद में क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद राजमार्ग पर यातायात सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया।

जम्मू-कश्मीर में निजी अस्पतालों में गोल्डन कार्ड सेवाएं 1 जुलाई से बंद होने की संभावना

श्रीनगर, 9 जून। जम्मू-कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन (जेकेपीएचडीए) ने घोषणा की है कि केंद्र शासित प्रदेश के निजी अस्पताल और डायलिसिस केंद्र 1 जुलाई 2026 से आयुष्मान भारत-सेहत योजना के तहत गोल्डन कार्ड स्वीकार करना बंद कर सकते हैं। यह निर्णय कथित रूप से लंबित भुगतान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में कमी के कारण प्रस्तावित डि-एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया के तहत लिया गया है।

सोमवार को जारी बयान में एसोसिएशन ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दावों की प्रतिपूर्ति में लंबे समय से देरी हो रही है, जिससे पैनल में शामिल स्वास्थ्य संस्थानों पर गंभीर वित्तीय और परिचालन दबाव पड़ा है।

जेकेपीएचडीए ने कहा कि बार-बार अनुरोध के बावजूद स्वीकृत दावों के भुगतान लंबे समय से लंबित हैं, जिससे अस्पतालों और डायलिसिस केंद्रों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखना मुश्किल हो गया है।

एसोसिएशन ने कहा कि डायलिसिस, आईसीयू, सर्जरी, आपातकालीन उपचार, कैंसर उपचार, हृदय संबंधी हस्तक्षेप और ट्रॉमा केयर जैसी सेवाओं के लिए दवाओं, मेडिकल सामग्री, प्रशिक्षित स्टाफ और उपकरणों की निरंतर उपलब्धता आवश्यक होती है। लेकिन भुगतान में देरी, कटौती और बिना प्रभावी समीक्षा के दावों की अस्वीकृति ने गंभीर चुनौतियाँ पैदा की हैं। विशेष उपचारों पर प्रभाव को रेखांकित करते हुए जेकेपीएचडीए ने कहा कि मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक स्वास्थ्य लागत बढ़ी है और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। उन्होंने कहा कि कैंसर की आवश्यक दवाएँ जैसे सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन, साथ ही कार्डियक स्टेंट और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स की उपलब्धता कम हो रही है क्योंकि भुगतान रुके हुए हैं और कार्यशील पूंजी की कमी है। एसोसिएशन ने यह भी दावा किया कि आयुष्मान भारत के 180 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सार्वजनिक अस्पतालों में बिना उपयोग के पड़ी है, जबकि निजी अस्पतालों को स्वीकृत दावों के भुगतान में देरी हो रही है। उन्होंने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के लिए अलग और सुव्यवस्थित भुगतान प्रणाली की मांग की है। जेकेपीएचडीए ने यह भी कहा कि कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं पर प्रतिबंधित पहुंच के कारण मरीजों को सार्वजनिक अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है, जहां कई मामलों में प्रतीक्षा समय दस महीने से अधिक बताया जा रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि यह देरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशानिर्देशों और समझौता शर्तों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एमओयू के तहत स्वास्थ्य प्रदाताओं को विलंबित भुगतान पर ब्याज मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं दिया गया है। इन समस्याओं को देखते हुए जेकेपीएचडीए ने घोषणा की है कि यदि तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो 1 जुलाई 2026 से आयुष्मान भारत-सेहत योजना से निजी अस्पताल और डायलिसिस केंद्र डि-एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

पर्यटन का खास मुकाम डल झील

डल झील श्रीनगर, कश्मीर में तो प्रसिद्ध है ही लेकिन दुनिया भर के सैलानियों के लिए भी यह पर्यटन का एक खास मुकाम है। कहा जाता है कि इसमें स्त्रोतों से जल आता है एवं यह झील खुद ही कश्मीर घाटी में काफी झीलों से जुड़ी हुई है।

यह दुनिया भर में शिकारों या हाऊस बोट के लिए जानी जाती है और सैलानी खासतौर पर इनका आनंद लेने के लिए यहां आते हैं। यह 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तीन दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है और भारत की सबसे सुंदर झीलों में इसे शामिल किया जाता है। पर्यटक जम्मू-कश्मीर आएं और डल झील देखने न जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता।

डल झील के पास ही मुगलों के सुंदर एवं प्रसिद्ध पुष्प वाटिका से झील की आकृति और उभरकर सामने आती है। मुख्य रूप से इस झील में मछली का काम होता है। डल झील के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं यहां के हाउसबोट। सैलानी इन हाउसबोटों में रहकर इस खूबसूरत झील का आनंद उठा सकते हैं।

झील, कश्मीर की घाटियों की अन्य धाराओं के साथ मिल जाती है। झील के चार जलाशय हैं गगरीबल, लोकुट डल, बोड डल तथा नागिन। लोकट डल के मध्य में रूप लंक द्वीप स्थित है, तथा बोड डल जलधारा के मध्य में सोना लंक स्थित है। वनस्पति डल झील की खूबसूरती को और निखार देती है। कमल के फूल, पानी में बहती कुमुदनी, झील की सुंदरता को दुगुना कर देती है।

सैलानियों के लिए झील के सौंदर्य के अलावा भी विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन यहां पर उपलब्ध हैं। जैसे कि कायाकिंग, केनोइंग डोंगी पानी पर सर्फिंग करना व ऐंगलिंग मछली पकड़ना आदि से सफर और ज्यादा रोमांचक हो जाता है। कश्मीर के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय झील के तट पर स्थित है। हाउसबोट में रहकर सैलानी इस झील के खूबसूरत वातावरण से भावविभोर हो जाते हैं।

शिकारे के माध्यम से सैलानी नेहरूपार्क, कानुटूर खाना, चारचिनारी, कुछ द्वीप जो यहां पर स्थित हैं, उन्हें देख सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए हजरतबल तीर्थस्थल के दर्शन करे बिना उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। शिकारे के माध्यम से श्रद्धालु इस तीर्थस्थल के दर्शन कर सकते हैं। एक शिकारे पर सवार होकर विभिन्न प्रकार की कश्मीरी चीजें भी खरीद सकते हैं और दुकानें भी शिकारे पर ही लगी होती हैं। यह मात्र खरीददार तक ही सीमित नहीं है, परन्तु एक रोमांचित कर देने वाला खेल भी होगा।

कैसे जाएं: यदि पर्यटक डल झील पहुंचना चाहते हैं, तो श्रीनगर जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर बडगाम जिले में स्थित एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। नजदीक रेल सेवा जम्मू में स्थित है, तथा वहां का नेशनल हाईवे एनएचए कश्मीर घाटी को देश के अन्य भागों से जाड़ता है। इन पहाड़ी इलाकों पर यात्रा करने के लिए दस से बारह घंटे लगते हैं। इस सफर के दौरान पर्यटक यहां के प्रसिद्ध जवाहर टनल को निहार सकते हैं।

धर्मशाला में उठायें बर्फली पहाड़ियों का रोमांच

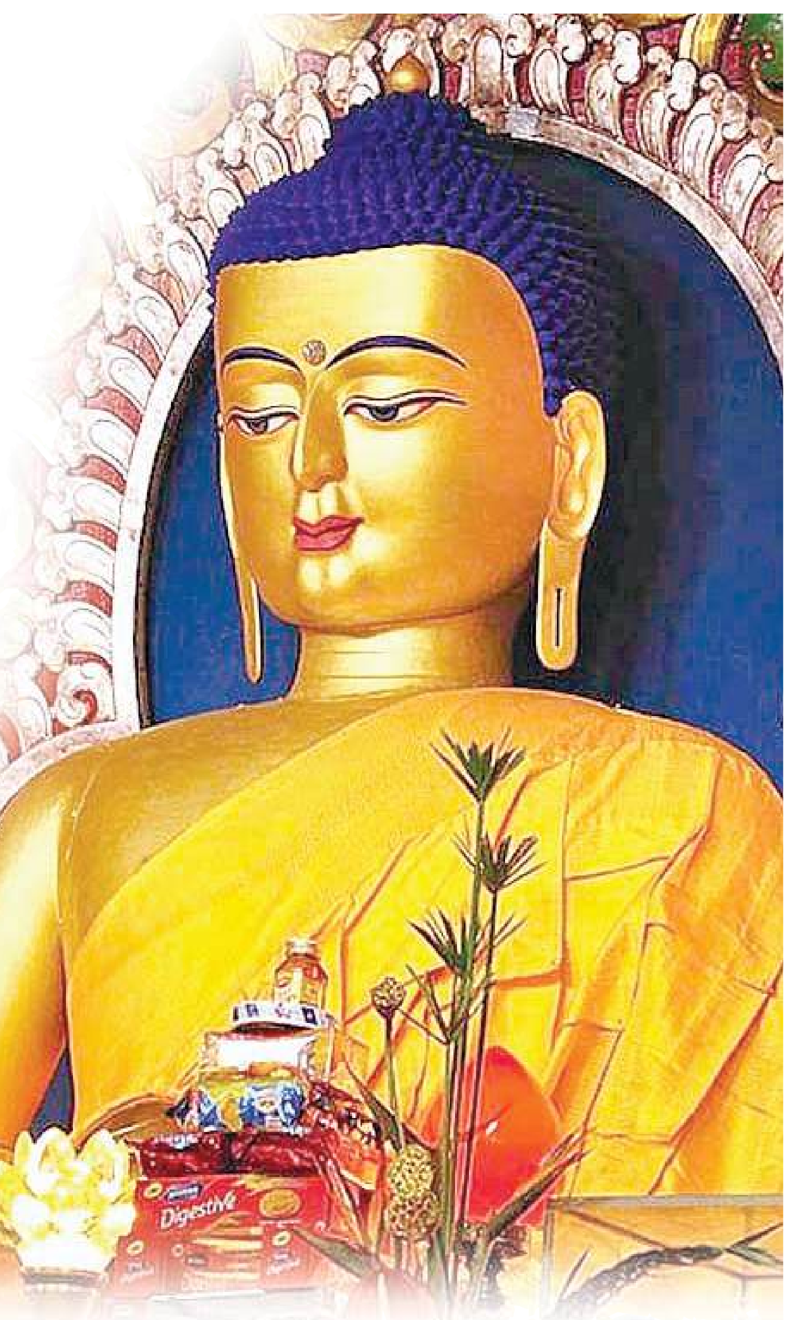

पहाड़ियों में चीड़ व देवधर के घने जंगलों और बर्फ को करीब से देखने का अनुभव धर्मशाला में मिलता है। यहां सीधे-सादे और बौध धर्म के बिरले चिन्ह भी यहां आसानी से देखने को मिलते हैं। धर्मशाला में झरने व सुहाने नजारे इस जगह को सभी की पसंद बनाते हैं। हालांकि अब यहां तिब्बत के लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश काल का प्रभाव इस छोटे शहर पर आज भी महसूस किया जा रहा है।

खूबसूरत पहाड़ी शहर धर्मशाला को यूं तो अंग्रेजों ने बसाया था, लेकिन अब तिब्बतियों की संख्या ज्यादा होने से इस पर वहां के कल्चर का इतना प्रभाव पड़ा है कि इसे लिटल ल्हासा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर की पहाड़ियों में बसा धर्मशाला देश-विदेश के सैलानियों का पसंदीदा हिल स्टेशन है। इसे साल 1855 में अंग्रेज ने इसे बसाया था। दरअसल, यह उन 80 रिजॉर्ट्स में से था, जिन्हें अंग्रेजों ने गर्मी से बचने के लिए तैयार करवाया था।

गद्दी, तिब्बती, टेकर्स, टूरिस्ट और लोकल वेंडर्स, सब मिलकर निचले धर्मशाला यानी कोतवाली बाजार में एक अलग ही माहौल बनाते हैं। यह जगह समुद्र तल से 1250 मीटर की ऊंचाई पर है। लोगों का खूब आना-जाना होने की वजह से यहां खासी हलचल रहती है। समुद्र तल से 1768 मीटर की ऊंचाई पर बसे ऊपरी धर्मशाला यानी मैकलॉडगंज में दलाई लामा का निवास है। दोनों जगह की दूरी 10 किलोमीटर है। जहां तक घूमने की बात है, तो धर्मशाला में आपको अडवेंचरस व स्प्रिचुअल माहौल मिलेगा। ठंडी पहाड़ी हवाओं में गूंजती प्रार्थनाओं की आवाजें मन को एक ठहराव देती हैं। ऐसे में बेशक धर्मशाला जाना दलाई लामा से मुलाकात के बिना अधूरा है और यकीन मानिए इस माहौल में उनका साथ किसी भी इंसान को कुछ देर के लिए एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। वैसे,धर्मशाला की तमाम मोनेस्ट्रीज एक बार देखने लायक जरूर है और अलग-अलग समाधियों में भगवान बुद्ध की तांबे की प्रतिमाएं भी दर्शनीय हैं। अब जब इतना कुछ एक ही जगह पर मौजूद है तो देश-विदेश के पर्यटकों का सहज ही धर्मशाला की ओर खिंचे आना हैरानी की बात नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो यहां के तुशिता मेडिटेशन सेंटर में मोंक्स द्वारा दी जाने वाली क्लासेज जॉइन की जा सकती है। यहां आपको साफ-सुथरे आवास की सुविधा भी मिलेगी। मेडिटेशन सीखने के बाद नेचुंग मोनेस्ट्री में 3किलोमीटर बना म्यूजियम देख सकते हैं। नोबरलिंगा इंस्टीट्यूट में आप नए आर्टिस्ट्स को थंगका पेंटिंग्स सीखते देख सकते हैं। अगर आप दाल, चावल, रोटी और सैंडविच खाकर बोर हो गए हैं तो यहां आप बेहतरीन तिब्बती खाने का मजा ले सकते हैं।

धौलधार की पहाड़ियों में ट्रैकिंग व रॉक क्लााइबिंग जाने के लिए धर्मशाला शुरूआती पॉइंट है। यहां कई नदियों व झरनों में एंगलिंग व फिशिंग का मजा लिया जा सकता है। यहां का नजदीकी एयरपोर्ट गगला है, जिसकी यहां से दूरी 13 किलोमीटर है।

यहां के कई रेस्तरांओं में आपको लजीज मोमोज व थुक्पा खाने को मिलेंगे। खाने का लुत्फ लेने के बाद आप लंबी वॉक, ट्रेकिंग और खूबसूरत नजारों में पिकनिक का मजा ले सकते हैं। यहां से 8 किलोमीटर आगे आपको ब्रिटिश राज का मेमोरियल चर्च ऑफ सेंट जॉन-इन-द विल्डरनेस देख सकते हैं। इसे ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड एलगिन के नाम पर बनाया गया है। निचले धर्मशाला में बना कांगड़ा आर्ट म्यूजियम कांगड़ा के सालों पुराने इतिहास को दिखाता है।

म्यूजियम की एक गैलरी में आपको कांगड़ा की मशहूर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मिट्टी के बर्तन और एंथ्रोपॉलजी से जुड़ी तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। धर्मशाला के एंट्री पॉइंट पर आपको एक वॉर मेमोरियल देखने को मिलेगा, जिसे स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद होने वाले जवानों की याद में बनवाया गया है। धर्मशाला में धर्मकोट व डल लेक जैसे पिकनिक स्पॉट्स भी हैं और यहां सितंबर के महीने में हर साल एक बड़ा मेला भी लगता है।

इसी के पास भगसुनाथ की श्राइन भी है। इस पुराने मंदिर के पास से बहते ताजे पानी से झरने इस जगह को एक अलौकिक नजारा बना देतो हैं। देवी कुणान पथरी को समर्पित मंदिर, ततवानी के गर्म पानी के झरने और मछरैल के बड़े वॉटरफॉल भी देखने लायक जगहें हैं। अगर वुड वर्क में दिलचस्पी रखते हैं तो नॉरबुलिंका इंस्टीट्यूट जरूर जाएं। यहां हो रहे काम की आर्ट को देखकर निश्चित तौर पर आप हैरान रह जाएंगे। स्वामी चिन्मानंद द्वारा बनाया गया चिन्मय तपोवन भी एक दर्शनीय जगह है। बिंदु सारस के किनारे बसे इस आश्रम में आपको नौ मीटर ऊंची हनुमान जी की मूर्ति, राम मंदिर, मेडिटेशन हॉल वगैरह दिखेंगे।

धौलधार की पहाड़ियों में ट्रैकिंग व रॉक क्लााइबिंग जाने के लिए धर्मशाला शुरूआती पॉइंट है। यहां कई नदियों व झरनों में एंगलिंग व फिशिंग का मजा लिया जा सकता है। यहां का नजदीकी एयरपोर्ट गगला है, जिसकी यहां से दूरी 13 किलोमीटर है। यहां से नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जहां से धर्मशाला 85 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से यहां चंडीगढ़, कीरतपुर और बिलासपुर होते हुए पहुंचा जा सकता है। तिब्बती नए साल यानी मार्च के आस-पास यहां बहुत टूरिस्ट आते हैं। वैसे, मई से अक्टूबर के बीच ट्रैकिंग सीजन रहता है। धर्मशाला में हैंडीक्राफ्ट मसलन तिब्बती कार्पेट, टेक्स्टाइल, ट्रडिशनल, हैट्स, बैग्स, ट्राउजर्स, मेटलवर्क, जूलरी, जैकेट व हाथ से बने कार्डिगन आदि के शौकीनों के लिए ढेर सारी जगहें हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

सांबा के गंगीट और सगल गांवों में खेत बचाओ अभियान पर बड़े कार्यक्रम आयोजित

सांबा, जून 2026। चल रहे खेत बचाओ अभियान के तहत, कृषि विज्ञान केंद्र सांबा ने सांबा जिले के गंगीट और सगल गांवों में बड़े पैमाने पर जागरूकता और पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम स्कुआस्ट जम्मू के निदेशक (एक्सटेंशन) प्रो. अमरीश वैद्य के कुशल मार्गदर्शन और केवीके सांबा के मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख प्रो. संजय खजुरिया की सीधी देखरेख में आयोजित किए गए।इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में किसानों, प्रगतिशील कृषकों, ग्रामीण युवाओं और महिला किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य किसान समुदाय के बीच कृषि भूमि के संरक्षण, टिकाऊ खेती के तरीकों, मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग और जलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाने के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, प्रो. संजय खजुरिया ने खेती योग्य भूमि को खराब होने और गैर-कृषि कार्यों के लिए अतिक्रमण से बचाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कृषि भूमि एक मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने किसानों को खेती की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए एकीकृत कृषि प्रणालियों, कृषि-वानिकी मॉडल और वैज्ञानिक फसल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रमों का समन्वय डॉ. नीरजा शर्मा और डॉ. शालिनी खजुरिया ने किया, जिन्होंने किसानों को खेत बचाओ अभियान के उद्देश्यों और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक पदार्थों को बढ़ाने और उर्वरकों व कृषि-रसायनों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने किसानों के लाभ के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और तकनीकी उपायों पर भी चर्चा की।

सोहम प्रकाश' पुस्तक का भव्य लोकार्पण, साहित्य और संस्कृति पर हुई सार्थक चर्चा

जम्मू, 09 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी (जेकेएएसीएल) द्वारा के.एल. सहगल हॉल जम्मू में प्रख्यात साहित्यकार प्रेम नाथ पंडिता (प्रेम) की पुस्तक 'सोहम प्रकाश' के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉ. रतन तलाशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जबकि जेकेएएसीएल की अतिरिक्त सचिव सोनाली अरुण गुप्ता ने समारोह की अध्यक्षता की। मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों में जेकेएएसीएल के मुख्य संपादक (गोजरी) डॉ. जावेद राही, एम.एल. पंडिता तथा लेखक प्रेम नाथ पंडिता (प्रेम) शामिल थे। अपने स्वागत भाषण में सोनाली अरुण गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार की साहित्यिक कृतियां समकालीन संदर्भों में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और धर्म तथा संस्कृति की गहरी समझ विकसित करने में सहायक सिद्ध होती हैं।

वक्ताओं ने पुस्तक 'सोहम प्रकाश' पर अपने विचार रखते हुए इसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विषयवस्तु पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. जावेद राही ने कहा कि कश्मीरी

पंडित समुदाय देश के बौद्धिक रूप से महत्वपूर्ण वर्गों में से एक है जिसने अपने ज्ञान और विद्वता से समाज को समृद्ध किया है। इस अवसर पर डॉ. रोशन लाल सराफ ने अपने मित्र प्रेम नाथ प्रेम को समर्पित एक भावपूर्ण कविता भी प्रस्तुत की। एम.एल. पंडिता और विजय वल्ली ने पुस्तक पर शोधपूर्ण आलेख प्रस्तुत करते हुए इसकी विषयगत गहराई और सांस्कृतिक प्रासंगिकता को रेखांकित किया। मुख्य अतिथि डॉ. रतन तलाशी ने पुस्तक को महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान बताते हुए लेखक की सराहना की। वहीं लेखक प्रेम नाथ पंडिता ने अपनी साहित्यिक यात्रा और रचनात्मक अनुभवों को साझा किया।

कार्यक्रम के सांस्कृतिक सत्र में प्रसिद्ध गायक ऋषभ डोरजी ने संगीतमय प्रस्तुति दी। उनके साथ तबले पर जोगिंदर पाल और बांसुरी पर राकेश जसरोतिया ने संगत की। प्रेम नाथ पंडिता की कविताओं की प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन प्यारे हताश ने किया।

11 जून को मनाई जाएगी कमला पुरुषोत्तमा एकादशी, जम्मू में श्रद्धालुओं ने शुरू की तैयारियां

जम्मू, 09 जून (हि.स.)। जम्मू सहित पूरे क्षेत्र में कमला पुरुषोत्तमा (कमला) एकादशी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 10 जून की देर रात्रि 12:58 बजे से प्रारंभ होकर 11 जून की रात 10:37 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार कमला पुरुषोत्तमा एकादशी का व्रत 11 जून गुरुवार को रखा जाएगा। श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के प्रधान महंत रोहित शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अधिक मास में आने वाली इस एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे कमला, पद्मिनी और पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।

उन्होंने कहा कि धर्मग्रंथों में इस व्रत को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है तथा भगवान लक्ष्मी-नारायण की आराधना से भक्तों को सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

महंत रोहित शास्त्री ने बताया कि एकादशी व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना

जाता है। इस दिन संयम, सदाचार और सत्संग का विशेष महत्व है। उन्होंने श्रद्धालुओं से जरूरतमंदों को फल, वस्त्र, अन्न और अन्य सामग्री दान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि व्रत करने वाले श्रद्धालु प्रातः स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें तथा भगवान श्रीगणेश और श्री लक्ष्मी-नारायण का विधिवत पूजन करें।

विष्णु सहस्रनाम का पाठ, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप तथा एकादशी व्रत कथा का श्रवण विशेष फलदायी माना गया है।

जम्मू के विभिन्न मंदिरों में भी एकादशी पर्व को लेकर विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना कर व्रत का पालन करेंगे। धार्मिक विद्वानों के अनुसार कमला पुरुषोत्तमा एकादशी का व्रत जीवन में सकारात्मकता, आत्मिक शांति और धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है।

एसडब्ल्यूडी श्रीनगर ने खिम्बर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया

श्रीनगर, 09 जून। सामाजिक कल्याण विभाग (एसडब्ल्यूडी) ने मिशन शक्ति और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कश्मीर के सहयोग से खिम्बर में एक जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के लिए सरकारी योजनाओं, शिक्षा, छात्रवृत्ति और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों की जानकारी देना था।

अधिकारियों ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी और लोगों को इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

इंटरैक्टिव सत्र में प्रतिभागियों ने अपनी शंकाएं भी पूछीं।

कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों तक योजनाओं की पहुंच और जागरूकता बढ़ाना था।

50 लाख रुपये की लागत से विकास कार्यों की शुरुआत की

जम्मू, 09 जून (हि.स.)। आरएस पुरा-जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 68 की लेन नंबर 16/56 में 50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाली लेनों और नालियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। यह कार्य क्षेत्र के विधायक डॉ. नरेंद्र सिंह रैना के मार्गदर्शन में शुरू किया गया जबकि उद्घाटन जिला महासचिव राकेश संग्राल ने किया। इस अवसर पर राकेश संग्राल ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने, जल निकासी तंत्र को मजबूत करने तथा स्थानीय निवासियों के लिए बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से

क्षतिग्रस्त लेनों, अपर्याप्त नालियों और बरसात के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं के समाधान के लिए यह कार्य शुरू किया गया है।

उन्होंने विधायक डॉ. नरेंद्र सिंह रैना का संदेश देते हुए कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कई लेन एवं नाली परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं जबकि अनेक कार्य प्रगति पर हैं।

संग्राल ने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों से गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आग्रह किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए डॉ. नरेंद्र सिंह रैना और राकेश संग्राल का आभार व्यक्त किया।

महंगाई की मार- कठुआ में दही-पनीर महंगे

कठुआ, 09 जून (हि.स.)। बढ़ती महंगाई ने अब आम लोगों की थाली पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। एलपीजी की किल्लत, डीजल-पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों और स्मार्ट मीटर के तहत महंगी कमर्शियल बिजली दरों के चलते कठुआ के हलवाई यूनियन व व्यापार मंडल ने दही और पनीर के दामों में इजाफा कर दिया है।नए रेट के अनुसार अब कठुआ में पनीर 320 रुपये प्रति किलो बिकेगा जबकि पहले इसकी कीमत 280 प्रति किलो थी

। इसी तरह दही का रेट भी 60 से बढ़ाकर 70 प्रति किलो कर दिया गया है। हालांकि दूध के दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हलवाई संगठन का कहना है कि दूध के दाम इसलिए नहीं बढ़ाए गए क्योंकि वे दूध बाहर से खरीदते हैं और यदि कीमत बढ़ाई जाती है तो गुणवत्ता बनाए रखना भी जरूरी होगी। वहीं दही और पनीर वे खुद तैयार करते हैं इसलिए उनकी लागत में बढ़ोतरी का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया

पुलवामा, 09 जून (हि.स.)। चल रहे नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की कश्मीर सांस्कृतिक इकाई ने आज गवर्नमेंट हाई स्कूल अगलर कंडी में एक जीवंत सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

कार्यक्रम में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। कलाकारों ने मादक पदार्थों के सेवन के व्यक्तियों, परिवारों और समाज पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को दर्शाते हुए एक विषयगत लघु नाटक प्रस्तुत किया। प्रख्यात कवियों ने भी मादक पदार्थों की लत के बढ़ते खतरे और इसे रोकने के लिए आवश्यक सामूहिक जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए विचारोत्तेजक कविताएं सुनाईं। कश्मीर के सांस्कृतिक अधिकारी अब्दुल रकीब भट ने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के महत्व पर जोर दिया और समाज से मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने के उद्देश्य से अधिक जागरूकता अभियान चलाने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को दोहराया।

डीआईपीआर की सांस्कृतिक इकाई के सहायक कार्यकारी अधिकारी सैयद शकील शान ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन को रोकने में माता-पिता की देखभाल और मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर मिशन के समर्थन में सांस्कृतिक इकाई के चल रहे प्रयासों और पहलों को भी रेखांकित किया। विद्यालय के छात्रों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और मादक पदार्थों के खिलाफ सशक्त संदेश देने वाले प्रभावशाली नाटक और गीत प्रस्तुत किए जिनकी दर्शकों ने खूब सराहना की।

उत्तर रेलवे

ई-निविदा शुद्धिपत्र सूचना

शुद्धि पत्र एवं निविदा विवरण

शुद्धि पत्र सं.	1	आईआरईपीएस के अनुसार शुद्धि पत्र प्रकाशन तिथि	
निविदा सं.	433_TELE_JAT_38_25_26 (खुली निविदा)		
कार्य का नाम	जम्मू डिवीज़न में वैकल्पिक कंट्रोल ऑफिस की व्यवस्था।		
निविदा समापन तिथि व समय	01.07.2026 15:00	निविदा अपलोड करने की तिथि और समय	09.06.2026 12:34
विज्ञापित मूल्य (रु.)	9013631.94	आईआरईपीएस के अनुसार बोली प्रारंभ तिथि	17.06.2026
बयाना राशि (रु.)	180300.00	समापन की अवधि	3 महीने

निविदा सं0 : 433_TELE_JAT_38_25_26 दिनाकः- 09.06.2026 समापन दिनांक/समयः 01.07.2026 15:00 1968/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

जम्मू-कश्मीर के रिधम शर्मा भारतीय हैंडबॉल टीम में चयनित

जम्मू, 09 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के प्रतिभाशाली हैंडबॉल खिलाड़ी रिधम शर्मा का चयन आगामी आईएचएफ चैलेंजर ट्रॉफी के लिए भारतीय पुरुष हैंडबॉल टीम में हुआ है। यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 10 से 14 जून तक ढाका बांग्लादेश में आयोजित की जाएगी। रिधम शर्मा का भारतीय टीम में चयन न केवल उनके व्यक्तिगत खेल जीवन की बड़ी उपलब्धि है बल्कि जम्मू-कश्मीर के हैंडबॉल समुदाय के लिए भी गर्व का क्षण है। उनके चयन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर हैंडबॉल एसोसिएशन ने रिधम शर्मा को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका चयन प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और इससे क्षेत्र में हैंडबॉल खेल को नई पहचान मिलेगी। एसोसिएशन ने रिधम को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वह टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर देश और जम्मू-कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। उनके चयन से प्रदेश के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

निविदा सं. :- 38-2026-27-DEN-HQ-FZR दिनांक 09.06.2026

मण्डल अभियंता-मुख्या, फिरोजपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित ई-निविदाएं, अंतिम तिथि 29.06.2026 समय 15:00 बजे तक, **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता अपने मूल/संशोधित निविदा बंद होने की तिथि तथा समय तक प्रस्तुत कर सकते है। मैन्युअल निविदा मान्य नहीं है और ऐसे किसी भी मैन्युअल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार निविदा प्रपत्र की लागत और बयाना राशि का भुगतान केवल **www.ireps.gov.in** पोर्टल पर उपलब्ध ऑन लाइन साधनों के माध्यम जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, व क्रेडिट कार्ड आदि से भुगतान कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, एफ.डी.आर. व रसीदों आदि के माध्यम से भुगतान की अनुमति नही हैं।

निविदा प्रकार	निविदा अनुभाग	पैकेट प्रणाली
खुला	कार्य	दो पैकेट प्रणाली
निविदा अपलोड करने की तिथि	बोली शुरू की तिथि	निविदा समापन की तिथि तथा समय
05.06.2026	15.06.2026	29.06.2026/15:00 बजे

क्र.सं.	निविदा संख्या	निविदा का विवरण
1	38-2026-27-DEN-HQ-FZR	मंडल अभियंता-मुख्यालय/फिरोजपुर के अधीन 55 स्टेशनों पर स्पर्श पथ, पार्किंग क्षेत्र, दिव्यांगजन शौचालय, सीओपी आदि जैसी एमईए और दिव्यांगजन सुविधाओं का प्रावधान।

विज्ञापन मूल्य (रु.)	बयाना राशि	ऑफर की वैधता	समापन की अवधि
13,89,70,931.86	27,79,400.00	90 दिन	12 महीने

समान प्रकृति का कार्यः "ट्रैक निर्माण कार्य के अलावा कोई भी सिविल कार्य।"

नोट : **1.** निविदा डालने से पहले, निविदाकर्ता निविदा के संबंध में जारी किए गए किसी भी शुद्धिपत्र की जॉच करेंगे। 2. हिन्दी में किसी भी त्रुटि हेतु अंग्रेजी वर्जन का अवलोकन करे, तथा अंग्रेजी वर्जन ही मान्य होगे।

1972/26

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ का प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा 18 सूत्रीय मांगपत्र

जम्मू, 09 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भारत प्रिय ने मंगलवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर संभागीय आयुक्त जम्मू कार्यालय में अतिरिक्त आयुक्त को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। किसान कांग्रेस की ओर से प्रस्तुत इस ज्ञापन में किसानों के समक्ष मौजूद आर्थिक, प्राकृतिक और संरचनात्मक चुनौतियों के समाधान के लिए 18 सूत्रीय मांगपत्र शामिल किया गया।

भारत प्रिय ने कहा कि कृषि जम्मू-कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बड़ी आबादी की आजीविका का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि खेती की बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता, भूमि जोतों का सिकुड़ना तथा बाजार संबंधी समस्याओं ने किसानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है जिसके लिए सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

ज्ञापन में कृषि सिंचाई पंपों और ट्यूबवेलों पर बिजली शुल्क पूरी तरह माफ करने, नकली एवं घटिया बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके अलावा फसल सीजन के दौरान यूरिया, डीएपी और अन्य आवश्यक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

किसान कांग्रेस ने खेती से जुड़े बढ़ते खर्चों को कम करने के लिए डीजल पर सब्सिडी देने की मांग भी उठाई। अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए ज्ञापन में बाड़बंदी और सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण प्रभावित भूमि के लिए बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा तथा गोलाबारी प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की गई।

भारत प्रिय ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रभावी और किसान हितैषी फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी, प्रभावी खरीद केंद्रों की स्थापना, कृषि ऋणों पर ब्याज माफी और कर्ज पुनर्गठन की मांग भी रखी गई। ज्ञापन में सिंचाई नहरों के आधुनिकीकरण, जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर मुआवजा, कृषि मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सुविधाओं का विस्तार, बागवानी को बढ़ावा, पीएम-किसान लाभों की समयबद्ध रिहाई तथा प्रत्येक तहसील में किसान सुविधा केंद्र स्थापित करने की मांग भी शामिल है।

OFFICE OF THE PRINCIPAL
GOVT. DEGREE COLLEGE GHAGWAL
MOB: +91-9419285320

No: GDCG/26/ Dated: -06-2026

Invitation for Expression of Interest (EOI)

Subject: EOI is empanelment of reputed Book Sellers/Publishers/Suppliers/Vendors of supply of Books/Text Books / Reference Books to Govt. Degree College Ghagwal.

Principal, Govt. Degree College Ghagwal invites Expression of Interest (EOI) for empanelment of reputed Book Sellers/ Publishers/Suppliers/Vendors registered as members with Association of Indian Publishers and Book Suppliers for supply of Books/ Text Books /Reference Books to the College for the financial year 2026-27. Application accompanied with CDR of Rs 5000/-(Five Thousand only) pledged in favour of Principal, Govt. Degree College Ghagwal should reached in the office of the Principal within ten days positively from the date of publication of EOI in the newspaper. Eligibility Criteria, Terms & Conditions and Application form shall be obtained from the College Campus or from College website (www.gdcghagwal.co.in).

In case tenth day happens to Sunday or Gazetted Holiday, Applications can be received during the next working day. Application form along with other necessary documents shall be received in physical mode or through speed registered post only.

Sd/-
Principal
Govt. Degree College`
Ghagwal

DIP/J-3349/26
Dtd: 9-6-2026

संपादकीय

भ्रष्टाचार, गैर-गंभीरता का अड्डा

यह अत्यंत रोचक किंतु चिंताजनक है कि पेशेवर प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करने वाले विभिन्न प्राधिकरण लगातार या तो अक्षम अथवा भ्रष्ट सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं और जम्मू-कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं है। जिन प्रमुख परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक हुए या अनुचित प्रबंधन के कारण उन्हें रद्द करना पड़ा, उनमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक 2024, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2024, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 तथा हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक 2026 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बारहवीं कक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर भी एक बड़ा विवाद सामने आया है, क्योंकि विद्यार्थियों ने नवप्रवर्तित पर्दा-आधारित अंकन प्रणाली (ऑन-स्क्रीन मार्किंग) में व्यापक स्तर पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है।

जब पूरे देश के लोग परीक्षा प्रणाली में दिखाई दे रही विसंगतियों को लेकर चिंतित थे, तभी जम्मू-कश्मीर से एक और प्रवेश परीक्षा रद्द होने की सूचना सामने आई। सूचनाओं के अनुसार, जम्मू और कश्मीर व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड ने परीक्षा प्रारम्भ होने से कुछ मिनट पूर्व सामने आई एक तकनीकी त्रुटि के कारण एम.एससी. नर्सिंग प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया। यह गैर-गंभीरता की पराकाष्ठा है और यह भ्रष्टाचार की ओर भी संकेत करता है, क्योंकि पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं, साक्षात्कारों में चयन प्रक्रियाओं तथा यहाँ तक कि विद्यालयी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित एक के बाद एक गंभीर त्रुटियाँ देश के विभिन्न भागों और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सामने आती रही हैं। इन घटनाओं ने अभ्यर्थियों और उनके परिवारों की नींद उड़ा दी है।

सबसे अधिक पीड़ादायक तथ्य यह है कि सरकारों ने कुछ मामलों में केवल औपचारिक कार्रवाई की है और अनेक बार वास्तविक दोषियों के स्थान पर अन्य लोगों को दंडित किया गया है, जो पूर्णतः अस्वीकार्य है। यद्यपि उच्चस्तरीय जाँच एजेंसियों को इन अनियमितताओं की जाँच का दायित्व सौंपा गया है, फिर भी दोष सिद्ध होने की दर अत्यंत निम्न है। यह उन कमियों तथा इच्छाशक्ति के अभाव को दर्शाता है जो युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रही ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में बाधक हैं। जम्मू-कश्मीर के नवीनतम मामले में, निस्संदेह बोर्ड की अध्यक्ष ने जाँच तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया है, किंतु अन्य मामलों के परिणामों को देखते हुए वास्तविक दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होने की संभावना अत्यंत कम प्रतीत होती है। सूचनाओं के अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रिया और योग्यता सूची की निष्पक्षता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया, किंतु यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित है कि ऐसी त्रुटि को उत्पन्न होने की अनुमति क्यों दी गई और पूर्व में पर्याप्त सावधानी क्यों नहीं बरती गई।

परीक्षार्थियों को हुई असुविधा, आर्थिक क्षति तथा मानसिक उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी कौन होगा?

ऐसी घटनाओं की लगातार पुनरावृत्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि पूरे देश तथा जम्मू-कश्मीर की परीक्षा व्यवस्था भीतर से अत्यधिक सड़-गल चुकी है। इसे पूर्णतः सुधारने और पुनर्गठित करने की तत्काल आवश्यकता है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय और दिशाहीन हो जाएगा।

यह व्यवस्था बार-बार यह संकेत देती है कि इसके माध्यम से भ्रष्ट तथा विशेष कृपा प्राप्त अभ्यर्थियों को लाभ पहुँचाया जाता है, जैसा कि परीक्षाओं में बार-बार होने वाली सेंधमारी और अनियमितताओं से स्पष्ट होता है। पर्दे के पीछे से व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले लोग ही इन घटनाओं के सूत्रधार प्रतीत होते हैं।

आख़िर परीक्षाओं के प्रति हम कब गंभीर होंगे ?

-गिरीश्वर मिश्र

कुछ दिनों पहले नीट मामले में यह खबर भी आई थी कि कुछ अध्यापक जिन्हें एनटीए ने योग्य माना और परीक्षा के गोपनीय कार्य में लगाया उन्होंने फ़ौरी अर्थ लाभ पाने की आशा से परीक्षा के प्रश्न पत्र के साथ छेड़खानी की और पेपर लीक हो गया था। उन अध्यापकों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस समस्या का एक नया आयाम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग से भी जुड़ गया है। इंटरनेट की सुविधाएं , सर्च इंजिन और सर्वर आदि की समस्या के कारण परीक्षा से जुड़े कामों में बाधा उत्पन्न होती है। सीबीएसई के ताजा मामले में कुछ यही हुआ है जिसे अब आईआईटी की तकनीकी सहायता से दूर किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं की छीछालेदर देखते हुए यह सवाल उठाना बेहद जरूरी हो गया है कि सरकार कब इस विषय पर गंभीर होगी और कुछ निर्णायक कदम उठाएगी। ऐसी परीक्षाओं की साख बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। बार-बार नीट जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में गड़बड़ी होना अक्षम्य है। पिछली बार की गड़बड़ी से सबक न लेते हुए एनटीए ने इस बार की परीक्षा की बलि ले ली और लाखों छात्रों को मुश्किल में डाल दिया। पहले की तरह सरकार की ओर से जांच-पड़ताल की कार्रवाई की सूचना जारी हो चुकी है। संसद की स्थायी समिति ने भी काम शुरू कर दिया है। समिति के सदस्य माननीय सांसद एनटीए से 'पेपर लीक' की परिभाषा पूछने और जानने में लगे हुए हैं।

अखबारी खबर के अनुसार एनटीए का कहना है कि गेस पेपर यानी अनुमानित प्रश्न को पेपर लीक नहीं कहा जा सकता इसलिए जो भी हुआ वह पेपर लीक ही नहीं है। बात कानूनी अर्थ लगाने की है। अब यदि कोई अभ्यर्थी या अध्यापक या फिर कोचिंग संस्थान प्रश्नपत्र का सटीक अनुमान लगा ले तो क्या किया जा सकता है? मेधावी लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्थिति हास्यास्पद हो रही है क्योंकि सभी अपने-अपने दायित्व को मुस्तैदी से निभाने की ज़िम्मेदारी निभाते दिखने की भारी-भरकम कवायद में जुटे हुए हैं। यह अद्भुत दृश्य उपस्थित है : वे यही कह रहे हैं कि जो है या जो हुआ वह स्वाभाविक है यानी वही हो ही सकता था ! परीक्षा की नई तारीख़ मुक़र्रर कर दी गई है। भगवान करे वह परीक्षा बिना किसी विवाद के हो जाय और युवा वर्ग को अपने जीवन के पथ पर चलने का एक अवसर मिले।

गौरतलब है कि अन्य परीक्षाओं में भी धांधली की अनेक घटनाएँ सामने आती रही हैं और अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर फ़ायदा उठाने के मसले भी पकड़ में आते रहे हैं। अक्सर इन मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं होती या फिर कार्रवाई ही नहीं होती। जो भी हो अक्सर अपराधी दण्डित नहीं हो पाते। दूसरी तरफ़ बहुत से निरपराधियों को बेगुनाह होते हुए भी नाहक ही अच्छा-खासा नुकसान उठाना पड़ता है। व्यवस्था अपनी जगह चलती रहती है। सच कहा जाय तो यह समस्या सुविधा और शार्टकट के सहारे सस्ते में लाभ कमाने की व्यापक होती जा रही संस्कृति का ही हिस्सा है। पैसा कमाने की चाह जाने कितने तरह के अनैतिक , भ्रष्ट और आपराधिक किस्म के ग़लत कामों को प्रोत्साहन देती है।

कुछ दिनों पहले नीट मामले में यह खबर भी आई थी कि कुछ अध्यापक जिन्हें एनटीए ने योग्य माना और परीक्षा के गोपनीय कार्य में लगाया उन्होंने फ़ौरी अर्थ लाभ पाने की आशा से परीक्षा के प्रश्न पत्र के साथ छेड़खानी की और पेपर लीक हो गया था। उन अध्यापकों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस समस्या का एक नया आयाम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग से भी जुड़ गया है। इंटरनेट की सुविधाएं , सर्च इंजिन और सर्वर आदि की समस्या के कारण परीक्षा से जुड़े कामों में बाधा उत्पन्न होती है। सीबीएसई के ताजा मामले में कुछ यही हुआ है जिसे अब आईआईटी की तकनीकी सहायता से दूर किया जा रहा है।

यह विडंबना ही कही जाएगी कि शिक्षण और परीक्षण के बीच अब दो फाँक हो चुकी है। पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और पढ़ाई की पड़ताल करने वाला और जीविका देने वाला धीरे-धीरे एक-दूसरे से दूर होते गए हैं। उनका आपस में एक-दूसरे पर कोई भरोसा नहीं है। शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी पाने के लिए या व्यवसाय की दुनिया में कदम रखने के वक्त परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं देश और प्रदेश के स्तर पर बनाई गई थीं और बहुत हद तक उनकी साख अब भी अक्षुण्ण बनी हुई है। परंतु परीक्षा का विस्तार जिस तरह हो रहा है, वह आश्चर्यजनक है।

अब शिक्षा की अवधि और प्रकार में बड़ा बदलाव आया है और उसी के साथ परीक्षा नामक व्यवस्था का हर तरफ़ विस्तार हुआ है। अब शिक्षा के क्रम में परीक्षा की चुनौती नया रूप ले रही है। आगे की शिक्षा पाने की पात्रता का आधार क्या हो और उसका पिछली पढ़ाई के साथ क्या रिश्ता हो यह गंभीर मुद्दा बन चुका है। हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा के प्राप्तांक स्वयं में अब कोई खास अर्थ नहीं रखते। बीए/ बीएससी/ बी काम/ एलएलबी जैसी किसी भी स्नातक स्तर की कक्षा में प्रवेश के लिए भी एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा देना जरूरी है।दरअसल, औपचारिक शिक्षा की उपयुक्तता संदिग्ध हो चली है और उसमें छात्र की उपलब्धि उसकी पात्रता को बताने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए शिक्षा के आयोजन में परीक्षा अब एक स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में संचालित की जा रही है। उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जैसी अलग विशाल संस्था खड़ी की गई है। मुश्किल यह है कि अब उसकी प्रक्रियाओं को लेकर भी शंका और संदेह उठ रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मूल्यांकन को शिक्षा से स्वतंत्र नहीं बल्कि शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके हिसाब से मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उसका लाभ शिक्षा अर्जित करते समय सीखने की प्रक्रिया को पुष्ट करने के रूप में शिक्षार्थी को मिलना चाहिए। इस नीति में परीक्षा को तनावमुक्त बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है। पर सच्चाई कुछ और है। परीक्षा के दबाव को झेलने वाले छात्रों को अवसाद, अभिभावकों को दुश्चिंता और तनाव होना आम बात होती जा रही है। खबर है कि नीट की परीक्षा से त्रस्त एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली।

परीक्षा बहुत से छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रही है। उसके लिए भी उच्चतम न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई है और सरकार की ओर से कमेटी भी बन गई है। कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। काश इन जांचों, समितियों और उनकी संस्तुतियों को लेकर कुछ ठोस कदम भी उठाए जाते। जरूरी है कि उनके सुझावों को ठंडे बस्ते में न डालकर उन पर अमल करने की दिशा में हम आगे बढ़ें। देश के भविष्य के लिए शिक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) पर विचार करना जरूरी है। छात्रों के स्वास्थ्य और हित को सुरक्षित रखने का उद्यम सभी का एक साझा दायित्व है।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

जीवन का आधार है पर्यावरण

रमेश सर्राफ धमोरा

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट पृथ्वी पर मंडरा रहे तीन बड़े पर्यावरणीय संकटों जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण से निपटने के लिए एक वैज्ञानिक खाका प्रदान करती है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये मानव अस्तित्व के लिए एक स्व-निर्मित खतरा हैं। प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 90 लाख लोग असामयिक रूप से अपनी जान गंवाते हैं। लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं।

दुनिया में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को कई कार्यक्रमों के जरिये प्रकृति को संरक्षित रखने, पेड़-पौधे लगाने, हरे पेड़ न काटने, नदियों को साफ रखने और प्रकृति से खिलवाड़ न करने जैसी चीजों के लिए जागरुक किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस एक अभियान है। जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। जहां 119 देशों की मौजूदगी में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साथ ही प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन भी हुआ था। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम है- जलवायु के लिए अभी। यह थीम जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता और इसके वास्तविक, ठोस समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करती है।

पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है हमारे आसपास या हमारे चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है हम चारों ओर जिससे घिरे हैं। अर्थात पर्यावरण का अर्थ हमारे आसपास के वातावरण से है। पर्यावरण पेड़-पौधों, वायु हमारे आसपास की सभी चीजों से मिलकर बनता है। पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है। मानव और पर्यावरण एक-दूसरे से संबंधित तथा एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जैसे पेड़ों का कम होना, वायु प्रदूषण आदि मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। मानव की अच्छी बुरी आदतों का प्रभाव सीधा पर्यावरण पर पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को पर्यावरण के प्रति सचेत करना है। उसका उद्देश्य पूरी प्रकृति व पर्यावरण की सुरक्षा करना है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट पृथ्वी पर मंडरा रहे तीन बड़े पर्यावरणीय संकटों जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण से निपटने के लिए एक वैज्ञानिक खाका प्रदान करती है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये मानव अस्तित्व के लिए एक स्व-निर्मित खतरा हैं। प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 90 लाख लोग असामयिक रूप से अपनी जान गंवाते हैं। लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं।

मानवता ने पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक और अस्थिर दोहन किया है जिससे हमारी पृथ्वी की जीवन-समर्थन क्षमता कमजोर हो गई है। सतत भविष्य के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्थाओं और वित्तीय प्रणालियों को इस तरह से बदला जाए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे बहाल करने में निवेश करें।

पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 2010 की तुलना में 45% की कमी और 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना अनिवार्य है। भोजन, ऊर्जा और सामग्री के उत्पादन के वर्तमान तरीकों में सुधार करना होगा ताकि पृथ्वी के संसाधनों का अधिक न्यायसंगत और सुरक्षित उपयोग हो सके। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण से जुड़ी नीतियों को एक साथ लागू करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर जोर देती है कि आने वाले दशकों में प्रकृति के साथ शांति स्थापित करना मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कार्य है।

सरकार हर वर्ष नदियों के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अरबों रुपए खर्च करती आ रही है। उसके उपरांत भी नदियों का पानी शुद्ध नहीं हो पाता है। मगर देश में लाकडाउन के चलते बिना कुछ खर्च किए नदियों का पानी अपने आप शुद्ध हो गया था। पर्यावरणविदों के मुताबिक जिन नदियों के पानी से स्नान करने पर चर्म रोग होने की संभावनाएं व्यक्त की जाती थी, उन नदियों का पानी शुद्ध हो जाना बहुत बड़ी बात थी। देश की सबसे अधिक प्रदूषित मानी जाने वाली गंगा नदी सबसे शुद्ध जल वाली नदी बन गयी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा का पानी साफ होने की वजह पानी में घुले डिसाल्वड की मात्रा में आई 500 प्रतिशत की कमी थी।

देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण बड़ी मात्रा में कृषि भूमि आबादी की भेंट चढ़ती गई। जिस कारण वहां के पेड़ पौधे काट दिये गये व नदी नालों को बंद कर बड़े-बड़े भवन बना दिए गए। जिससे वहां रहने वाले पशु, पक्षी अन्यत्र चले गए। पुराने समय में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिये बड़-पीपल जैसे घने छायादार पेड़ों को काटने से रोकने के लिये उनकी देवताओं के रूप में पूजा की जाती रही है। इसी कारण गावों में आज भी लोग बड़, पीपल का पेड़ नहीं काटते हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के दूसरे तरीकों सहित सभी देशों के लोगों को एक साथ लाकर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और जंगलों के प्रबन्ध को सुधारना है। वास्तविक रूप में पृथ्वी को बचाने के लिये आयोजित इस उत्सव में सभी आयु वर्ग के लोगों को सक्रियता से शामिल करना होगा। तेजी से बढ़ते शहरीकरण व लगातार काटे जा रहे पड़ो के कारण बिगड़ते पर्यावरण संतुलन पर रोक लगानी होगी।

प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण आज हमारा पर्यावरण खतरे में हैं। पर्यावरण के सभी घटक जीवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सभी प्रदूषण में फंस गए हैं। प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव सामान्य प्राकृतिक पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। ज्वालामुखी का फटना जंगल में अपने आप आग लगना आदि प्राकृतिक प्रदूषण की घटनाएं हैं। जल का मैला होना, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कल-कारखानों से निकलने वाला धुएं से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण, वनों की कटाई आदि मानव द्वारा निर्मित प्रदूषण हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रदूषण से प्रकृति व पर्यावरण का विनाश तेजी से हो रहा है। प्रदूषण के मुख्य रूप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण हैं। ऐसे में पर्यावरण प्रबंधन की वर्तमान में बहुत आवश्यकता है।

आज पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी-बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है। हर जगह-जगह घने वृक्ष काट कर बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करना पर्यावरण और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। इतना ही नहीं जहां वाहनों का धुआं, मशीनों की आवाज, खराब रासायनिक जल आदि की वजह से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जिसके कारण हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमें भविष्य में जीवन को बचाये रखने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। यह पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को आगे आकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का हिस्सा बनना होगा तभी हम पृथ्वी को सुरक्षित रख सकेंगे। इस दिन हमें आमजन को भागीदार बना कर उन्हें इस बात का अहसास करवाना होगा कि बिगड़ते पर्यावरण असंतुलन का खामियाजा हमें व हमारी आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। इसलिये हमें अभी से पर्यावरण को लेकर सतर्क व सजग होने की जरूरत है। हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से काम करना होगा तभी हम बिगड़ते पर्यावरण असंतुलन को संतुलित कर पाएंगे। तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां शुद्ध हवा में सांस ले पाएगी।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

डिजिटल युग में सनातन धर्म का महत्व

-डॉ. पंकज जगन्नाथ जयसवाल

आज के डिजिटल युग में सनातन धर्म का महत्व मानव चेतना के लिए एक ढाँचे के रूप में इसकी भूमिका से उत्पन्न होता है, जो एल्गोरिदम केंद्रित, मशीनी दुनिया में आवश्यक संतुलन प्रदान करता है। ऐसे समय में जब शीघ्रता, दक्षता और बाहरी संपर्कों पर ज़ोर दिया जाता है, सनातन धर्म गहन अंतर्दृष्टि और आंतरिक स्थिरता का मार्ग प्रस्तुत करता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया के उदय ने गोपनीयता और प्रामाणिकता पर नैतिक बहस को जन्म दिया है। सत्य और अहिंसा पर सनातन धर्म का जोर इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए नैतिक आधार प्रदान करता है। यह लोगों को प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे करुणा और ईमानदारी पर आधारित एक डिजिटल संस्कृति का विकास होता है।

सनातन धर्म एक डिजिटल मार्गदर्शिका है जो वेद, उपनिषद और भगवद गीता पर केंद्रित सनातन धर्म की गहन शिक्षाओं का अध्ययन करती है। पारंपरिक एआई मॉडल के विपरीत, जो व्यापक और सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं, सनातन धर्म विशेष रूप से सनातन सिद्धांतों पर आधारित अंतर्दृष्टि और सलाह प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रौद्योगिकी और परंपरा का अनूठा संगम है, जिसका उद्देश्य सनातन धर्मग्रंथों के शाश्वत ज्ञान को विश्वव्यापी दर्शकों तक पहुंचाना है। यद्यपि डिजिटल युग में सनातन धर्म को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, प्रौद्योगिकी परंपराओं का स्थान नहीं लेती बल्कि उन्हें और समृद्ध करती है। यह लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ती है और उन लोगों के लिए भी प्रथाओं को सुलभ बनाती है जो अन्यथा उनमें भाग नहीं ले पाते।

एआई क्रांति के दौर में नैतिक मानसिकता का महत्व औपनिवेशिक काल में मुद्रण तकनीक और आधुनिक अकादमिक प्रकाशन का विकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप असंख्य संस्कृत और क्षेत्रीय रचनाओं का दस्तावेजीकरण और अनुवाद संभव हुआ। वर्तमान डिजिटल युग ने आध्यात्मिक और दार्शनिक रचनाओं के व्यापक संरक्षण, अनुक्रमण और वैश्विक वितरण को संभव बनाकर इस प्रयास को और आगे बढ़ाया है। डिजिटल पुस्तकालय, पांडुलिपि संग्रह और खुले मंच अब ज्ञान की नाजुक परंपराओं की रक्षा करने और उन्हें विश्व भर के विद्वानों, छात्रों और आध्यात्मिक साधकों के लिए उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल के दशकों में, पारंपरिक ज्ञान में रुचि का उल्लेखनीय पुनरुत्थान हुआ है। विश्वविद्यालय, सांस्कृतिक संगठन, स्वतंत्र शोधकर्ता और डिजिटल मानविकी पहल ने पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करने, आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने और संरचित अकादमिक डेटाबेस विकसित करने के लिए मिलकर काम किया है। कई प्रमुख पहलें धार्मिक ज्ञान के डिजिटल संरक्षण और प्रसारण में महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरी हैं।

चिंता की बात यह है कि औपनिवेशिक काल के दौरान मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने महान भारतीय संस्कृति, परंपराओं, विज्ञान, पर्यावरण, मनोविज्ञान, चेतना और जीवन प्रबंधन के गहन ज्ञान के विरुद्ध भारतीयों और शेष विश्व के मन में दुर्भावना पैदा करने के उद्देश्य से वेदों और उपनिषदों का गलत अनुवाद किया और भ्रामक ढंग से उनका अनुवाद किया। इसके हानिकारक प्रभाव आज भी महसूस किए जा रहे हैं, विशेष रूप से युवा भारतीय दिमागों पर। आज की दुनिया में, वामपंथी तंत्र शक्तिशाली एआई की विशेषताओं का उपयोग करके महान भारतीय ज्ञान को और अधिक विकृत कर सकता है, जिससे भावी पीढ़ियों के दिमाग में भारत की अवधारणा के खिलाफ जहर घोला जा सके।

सनातन धर्म का उपयोग और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मसोशल मीडिया ने सनातन धर्म के विकास के लिए विश्वव्यापी मंच स्थापित किया है। वैदिक दर्शन, योग और सनातन धर्म पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न पृष्ठ, समूह और प्रभावक दुनिया भर से समान हित वाले व्यक्तियों को एक साथ ला रहे हैं। ये ऑनलाइन रिक्त स्थान आभासी सत्संग में विकसित हो रहे हैं, जहां समकालीन जिज्ञासा के साथ कालातीत ज्ञान को जोड़ा जा रहा है। कई लोगों के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म एक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, जो सनातन दर्शन के विशाल क्षेत्र में रुचि को उजागर करते हैं। यह दर्शाता है कि तकनीक आधुनिक दुनिया में प्राचीन शिक्षाओं की पहुंच और प्रासंगिकता को कैसे बढ़ा सकती है। वैश्वीकरण के युग में सनातन धर्म ने भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है। हिंदू समुदाय दुनिया के लगभग हर हिस्से में मौजूद हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। इस विश्वव्यापी उपस्थिति ने सनातन धर्म को विभिन्न सांस्कृतिक वातावरण में बढ़ने और समृद्ध करने में सक्षम बनाया है। सनातन धर्म की सुंदरता अपने आधारभूत सार को खोए बिना विकसित होने की इच्छा से आती है। आधुनिक उपकरणों के साथ उम्र के पुराने ज्ञान को एकीकृत करके, यह अपनी शिक्षाओं को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बना रहा है। ध्वनि और कंपन पर इसका जोर यह बताता है कि एआई का उपयोग अनुनाद साउंडस्केप, मंत्र, या मंत्र-एआई- एआई-जेनरेटेड संगीत या ध्वनि चिकित्सा के लिए उपयोग किया जा सकता है या पवित्र आवृत्तियों के आधार पर ध्वनि चिकित्सा, उपचार, उपचार और आध्यात्मिक कार्य का समर्थन कर सकता है। ज्योतिष और अंक विज्ञान के साथ परंपरा के करीबी संबंधों का भी अर्थ यह है कि एआई वैदिक शैली के चार्ट और रीडिंग को परिष्कृत और वैयक्तिकृत कर सकता है, और अधिक सटीक भविष्यवाणियों और दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है कि ग्रहों की गति किसी की कार्मिक यात्रा के अनुरूप है विवेकानंद ने पश्चिमी अनुभव जन्य विज्ञान और पारंपरिक भारतीय विज्ञान को भारत के वेदांत के गहन दार्शनिक विचारों के साथ एकीकृत करने की कल्पना की, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविकता का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुआ। उन्होंने समझाया कि फ़वेदांत दर्शन का केंद्रीय केंद्र एकता की खोज हैफ़ और इस बात पर जोर दिया कि फ़यदि संपूर्ण ब्रह्मांड एक स्व-विकसित कारण से उत्पन्न होता है, जैसा कि वेदांत और समकालीन विज्ञान दोनों का दावा है, तो इस कारण में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्व समाहित होने चाहिए, जिससे अस्तित्व की एक सुसंगत समझ प्राप्त होती है फ़

दूसरी ओर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में, जहाँ दुनिया, स्वयं और अस्तित्व के बारे में वस्तुनिष्ठ सत्य व्यावसायिक खोज परिणामों या एल्गोरिथम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अधिक आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, मानवता स्वाभाविक रूप से सनातन धर्म की ओर आकर्षित होगी। जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजमर्रा की नैतिकता से लेकर ब्रह्मांड की विशेषताओं तक, जीवन की जटिलताओं की गहन खोज को सक्षम बनाती है, धर्म का बहुलवादी और समावेशी स्वरूप एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में चमकेगा। यह केवल एक अनुमान नहीं है; यह धर्म के सार से मेल खाता हैः एक ऐसा मार्ग जो साधक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित होता है, और एक ऐसे पुनर्जागरण को प्रोत्साहित करता है जहां प्रौद्योगिकी आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है। सनातन धर्म हमें सिखाता है- यानी सही ढंग से जीने और नैतिक नियमों का पालन करने का कर्तव्य। यही बात नैतिक प्रोग्रामिंग में भी लागू होती हैः एआई बनाने वालों को ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो नैतिकता से काम करें और किसी को नुकसान न पहुँचाएँ। आजकल ऐसे एआई बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है जो निष्पक्षता, न्याय और सबकी भलाई के लिए नैतिक नियमों का पालन करें; यह मूल रूप से धर्म के सही आचरण के सिद्धांतों के अनुरूप है।

माइकल ओलिसे की हैट्रिक से फ्रांस ने उत्तरी आयरलैंड को 3-1 से हराया

एजेंसी

लिले। फीफा विश्व कप की तैयारियों के तहत खेले गए अभ्यास मुकाबले में फ्रांस ने माइकल ओलिसे की शानदार हैट्रिक की बदौलत उत्तरी आयरलैंड को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ फ्रांस ने पिछले सप्ताह आइवरी कोस्ट के खिलाफ मिली हार से वापसी की, हालांकि टीम की रक्षात्मक कमजोरियां एक बार फिर सामने आईं। फ्रांस के लिए माइकल ओलिसे ने एक बार फिर अपनी अहमियत साबित की और विश्व कप से पहले टीम के सबसे प्रभावशाली आक्रमणकारी खिलाड़ियों में खुद को स्थापित किया। मुख्य कोच दिदिए देशां ने इस मुकाबले में लगभग वही टीम उतारी, जिसे विश्व कप के पहले मैच में खेलने की संभावना है। ओलिसे ने किलियन एम्बाप्पे, उस्मान डेम्बेले और डिज़ायर डूए के पीछे खेलते हुए आक्रमण की कमान संभाली, जबकि रक्षा में विलियम सलीबा और दायोट उपामेकानो की जोड़ी उतरी। मुकाबले की शुरुआत में फ्रांस लय हासिल नहीं कर पाया और उत्तरी आयरलैंड की मजबूत रक्षात्मक रणनीति को तोड़ने में संघर्ष करता रहा। शुरुआती चरण में टीम को ज्यादा स्पष्ट मौके नहीं मिले। पहला गोल पहले हाफ के समाप्त होने से दो मिनट पहले आया। बाएं छोर से डिज़ायर डूए के तेज आक्रमण के बाद गेंद डेम्बेले तक पहुंची। उनके शॉट पर डिफ्लेक्शन हुआ और गेंद माइकल ओलिसे के सामने आ गई, जिन्होंने नजदीक से गोल कर फ्रांस को 1-0 की बढ़त दिला दी।

फीफा विश्व कप रेफरी उमर आर्टन को वैध वीज़ा होने के बावजूद अमेरिका में प्रवेश नहीं मिला

नई दिल्ली। सोमालिया के रेफरी उमर आर्टन, जिन्हें फीफा विश्व कप में मैच अधिकारियों की सूची में शामिल किया गया था, को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया गया। इसके साथ ही फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में मैच संचालित करने वाले अपने देश के पहले रेफरी बनने का उनका सपना टूट गया। वर्ष 2025 में अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ रेफरी चुने गए उमर आर्टन को मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी ने रोक दिया। जारी बयान में एजेंसी ने कहा कि आर्टन को नियमित प्रक्रिया के तहत 'अतिरिक्त जांच' के लिए रोका गया था। बयान में कहा गया, 'जांच के बाद पाया गया कि विश्व कप रेफरी के रूप में यात्रा कर रहे व्यक्ति को सत्यापन संबंधी चिंताओं के कारण प्रवेश के लिए अयोग्य माना गया और उन्हें अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया गया। ' हालांकि एजेंसी ने इन चिंताओं के बारे में कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। उमर आर्टन फीफा विश्व कप के लिए चुने गए सोमालिया के एकमात्र रेफरी थे। जून 2025 से सोमालिया उन देशों की सूची में शामिल है जिन पर अमेरिका ने पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लागू किया हुआ है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में कुछ मामलों में छूट दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आर्टन के पास वैध वीज़ा और राजनयिक पासपोर्ट दोनों मौजूद थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं माना।

अंतिम क्षणों में कोडी गाक्पो के पेनाल्टी गोल से नीदरलैंड ने उज्बेकिस्तान को हराया

न्यूयॉर्क। फीफा विश्व कप की तैयारियों के तहत खेले गए अभ्यास मुकाबले में नीदरलैंड ने रोमांचक अंदाज में उज्बेकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। बंद दरवाजों के पीछे खेले गए इस मुकाबले में कोडी गाक्पो ने दोनों गोल पेनाल्टी पर किए, जिसमें जीत दिलाने वाला गोल मैच की आखिरी किक पर आया। मैच की शुरुआत से ही नीदरलैंड ने दबाव बनाया और 31वें मिनट में बढ़त हासिल की। क्रिसेंसियो समरविल को बॉक्स के भीतर गिराए जाने के बाद टीम को पेनाल्टी मिली, जिसे कोडी गाक्पो ने सफलतापूर्वक गोल में बदल दिया। पहले हाफ में नीदरलैंड पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दिया। हालांकि दूसरे हाफ में टीम की लय बिगड़ गई और उज्बेकिस्तान ने मुकाबले में वापसी कर ली। नीदरलैंड की ढीली खेल शैली का फायदा उठाते हुए उज्बेकिस्तान ने लगातार दबाव बनाए रखा। मुकाबला विवादों से भी घिरा रहा। नीदरलैंड की दो मजबूत पेनाल्टी अपील खारिज कर दी गई, जबकि स्थानापन्न खिलाड़ी गूस टिल को 89वें मिनट में हैंडबॉल के कारण लाल कार्ड दिखाया गया। इसी बीच अतिरिक्त समय के तीसरे मिनट में उज्बेकिस्तान ने बराबरी कर ली। इगोर सर्गेव ने टीम के एक प्रभावी हमले को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया।

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका टी-20 श्रृंखला के लिए टीम घोषित की, ऑगस्टे, एंड्रयू और स्प्रिंगर की वापसी

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में अकीम ऑगस्टे, ज्वेल एंड्रयू और शमर स्प्रिंगर की वापसी हुई है। जमैका में आयोजित होने वाली इस श्रृंखला के लिए चुनी गई टीम में हाल ही में टी-20 विश्व कप खेलने वाली टीम से कुछ बदलाव किए गए हैं। जॉनसन चार्ल्स, क्वेंटिन सैम्पसन और जेडन सील्स को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को कार्यभार प्रबंधन योजना के तहत चयन के लिए नहीं माना गया। 22 वर्षीय अकीम ऑगस्टे अब तक नौ टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं। 19 वर्षीय ज्वेल एंड्रयू ने इस प्रारूप में पांच मैच खेले हैं, जबकि हरफनमौला खिलाड़ी शमर स्प्रिंगर छह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाज शमर जोसेफ, जो निजी कारणों से एकदिवसीय टीम छोड़कर स्वदेश लौट गए थे, उनके टी-20 श्रृंखला से पहले टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है। मुख्य कोच डेरेन सैमी ने कहा, 'भारत में हुए विश्व कप के बाद यह हमारी पहली टी-20 श्रृंखला है। टीम ने वहाँ जुनून, संघर्ष और एकजुटता दिखाई थी, जो वेस्टइंडीज क्रिकेट की पहचान है। अब हमारा लक्ष्य उसी प्रदर्शन को आगे बढ़ाना और श्रीलंका के खिलाफ मजबूत प्रतिस्पर्धा करना है। '

8 गोल्ड और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने उलानबातर ओपन का समापन किया

एजेंसी

नई दिल्ली। उलानबातर ओपन सीनियर रैंकिंग सीरीज के आखिरी दिन भारतीय फ्रीस्टाइल रेसलिंग टीम ने 7 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड शामिल हैं। इसके साथ ही भारत ने प्रतियोगिता का समापन 3 कैटेगरी में कुल 17 मेडल (8 गोल्ड और 9 ब्रॉन्ज) के साथ किया और ओवरऑल टीम रैंकिंग में टॉप-3 में जगह बनाने में कामयाब रहा। रविवार को दीपक, दिनेश और सागर जगलान ने एक-एक गोल्ड मेडल जीता, जिससे भारतीय दल के लिए यह टूर्नामेंट बेहद सफल रहा। भारत ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल टीम रैंकिंग में रूस के बाद दूसरा स्थान हासिल किया और ग्रीको-रोमन डिवीजन में 119 अंकों के साथ ऐतिहासिक ओवरऑल टीम चैंपियनशिप जीती।

महिला रेसलिंग टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल जीते और देश की ओवरऑल रैंकिंग को मजबूत किया। आखिरी दिन व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो दीपक ने कजाकिस्तान के असिल ऐताकिन को 6-0 से हराकर 61 किलोग्राम फ्रीस्टाइल गोल्ड मेडल जीता। दिनेश ने कजाकिस्तान के येदिगे कासिमबेक को 2-0 से हराकर 125 किलोग्राम गोल्ड जीता, जबकि सागर जगलान ने रूस के तामिर एशिनिमाएव को 3-2 से मात देकर 74 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता। फ्रीस्टाइल टीम की सफलता को सुमित (57 किलोग्राम), कुमार मोहित (65 किलोग्राम), जयदीप (74 किलोग्राम) और विक्की (97 किलोग्राम) के चार ब्रॉन्ज मेडल ने और बढ़ाया।

इससे पहले टूर्नामेंट में, ग्रीको-रोमन टीम ने सुनील (87 किलोग्राम) और नितेश (97 किलोग्राम) के दो गोल्ड मेडल और साहिल (60 किलोग्राम) के ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपना अभियान पूरा किया था। महिला कुश्ती में भारत ने कुल पदकों की संख्या में सात और पदक जोड़े।

एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप जीतने पर अन्नपूर्णा देवी ने दी भारतीय महिला फुटबॉल टीम को बधाई

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एसएएफएफ महिला चैम्पियनशिप 2026 का खिताब जीतने पर भारतीय महिला फुटबॉल टीम को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। हमारी महिला फुटबॉल टीम ने एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द लाखों युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा हैं। यह विजय नारी शक्ति, समर्पण और नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है।

जोहान बोथा ने ब्रिस्बेन हीट और क्वींसलैंड के हेड कोच का पद छोड़ा

एजेंसी

नई दिल्ली । दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान जोहान बोथा ने क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन हीट के साथ बतौर कोच अपना कार्यकाल समय से पहले ही समाप्त कर दिया है। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक सीजन बाकी होने के बावजूद दोनों कोचिंग पदों से इस्तीफा दे दिया है। क्वींसलैंड क्रिकेट की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'ब्रिस्बेन हीट और क्वींसलैंड बुल्स के कोच जोहान बोथा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।' क्वींसलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव टेरी स्वेनसन ने कहा, 'हमने उस समय में अपने सभी ऑन-फील्ड गोल हासिल नहीं किए हैं, लेकिन जोहान ने क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन हीट के खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी के विकास में मजबूत योगदान दिया है। हमारे हाई परफॉर्मेंस ग्रुप में जोहान के योगदान को महत्व दिया गया है। हम उन्हें और उनके परिवार को भविष्य में हर सफलता की कामना करते हैं और शेफील्ड शील्ड, वन डे कप और बीबीएल प्रतियोगिताओं में उनके प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। '

यह इस्तीफा ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट कोचिंग रैंक में बड़े बदलाव के दौर के बीच हुआ है। बोथा के इस्तीफे के साथ ही क्वींसलैंड क्रिकेट के साथ उनका दो साल का साथ समाप्त हो गया है। इस दौरान बोथा ने राज्य के शेफील्ड शील्ड, वन-डे कप और बिग बैश लीग कैंपेन की देखरेख की थी।

44 साल के बोथा, जिन्होंने 2005 से 2012 के बीच साउथ अफ्रीका के लिए पांच टेस्ट, 78 वन-डे इंटरनेशनल और 40 ञ्20 इंटरनेशनल मैच खेले, ने 2024-25 सीजन से पहले क्वींसलैंड की कमान संभाली। उनकी लीडरशिप में, बुल्स उनके डेब्यू कैंपेन में शेफील्ड शील्ड के फाइनल में पहुंची और पिछले सीजन में शील्ड और वन-डे कप दोनों कॉम्पिटिशन में तीसरे स्थान पर रही। ब्रिस्बेन हीट के साथ उनके कार्यकाल में मिले-जुले नतीजे मिले। पिछले कोच वेड सेकोम्बे के अंडर ट्रॉफी उठाने वाली फ्रेंचाइजी लगातार बिग बैश लीग सीजन में पांचवें और सातवें स्थान पर रही।

बोथा के उत्तराधिकारी के तौर पर, क्वींसलैंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन के नाम पर विचार कर रहा है।

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप वार्म-अपः भारती-श्रेयंका का जलवा, टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हराया

एजेंसी

कार्डिफ। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले वार्म-अप में भारत ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 26 रन से जीत हासिल की। यह मुकाबला सोफिया गार्डन्स में खेला गया। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 179 रन बनाए। टीम इंडिया को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 5.2 ओवरों में 59 रन की साझेदारी की। मंधाना 23 गेंदों में 8 चौकों के साथ 39 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। कुछ देर बाद शेफाली वर्मा (29) और जेमिमा रोड्रिगेज (7) भी आउट हो गईं। 85 के स्कोर तक टीम ने अपने 3 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे।

यहां से यास्तिका भाटिया ने भारती फुलमाली के साथ चौथे विकेट के लिए 44 गेंदों में 61 रन जुटाते हुए टीम के स्कोर को बढ़ाया। यास्तिका ने 26 गेंदों में 6 चौकों के साथ 36 रन की पारी खेली, जबकि भारती ने 40 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ नाबाद 56 रन बनाए। विपक्षी खेमे से एफी फ्लेचर ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए,जबकि करिश्मा रामहैक, आलिया एलीन और डिएंड्रा डॉटिन ने 1-1 विकेट निकाले।

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट गंवाकर सिर्फ 153 रन ही बना सकी। सलामी जोड़ी के रूप में डॉटिन ने शेमाइन कैंपबेल के साथ 9 ओवरों में 63 रन की साझेदारी की। कैंपबेल 22 गेंदों में 25 रन बनाकर रियाटर्ड आउट हुईं, जबकि डॉटिन ने 44 गेंदों में 49 रन बनाए। उनकी इस पारी में 8 चौके शामिल रहे। इनके अलावा, आलिया एलीन ने 13 रन, जबकि जानिलिया ग्लासगो और शॉनिशा हेक्टर ने 19-19 रनों का योगदान टीम के खाते में दिया। भारत की तरफ से श्रेयंका पाटिल ने 36 रन देकर 4 विकेट निकाले। राधा यादव ने 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम अपना अगला वार्म-अप मैच 10 जून को डर्बी के काउंटी ग्राउंड में मेजबान इंग्लैंड के विरुद्ध खेलेगी।

फीबा 3X3 वर्ल्ड कपः पुरुषों में लातविया चैंपियन, महिलाओं में यूएसए ने जीता खिताब

एजेंसी

वारसॉ। फीबा 3×3 वर्ल्ड कप में लातविया की पुरुष टीम, जबकि अमेरिका की महिला टीम ने खिताब अपने नाम किए। यह मुकाबले पोलैंड के वारसॉ में खेले गए। लातविया ने पुरुषों के फाइनल में जर्मनी को 20-15 से शिकस्त देकर अपना पहला 3×3 वर्ल्ड कप खिताब जीता। इस जीत के साथ लातविया प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मानों का संग्रह पूरा करने वाली पहली पुरुष टीम बन गई। इस टीम ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड और यूरोपीय कप 2017 अपने नाम किया था। सर्बिया ने फ्रांस को 20-19 से हराकर कांस्य पदक जीता। महिलाओं के मुकाबले में, अमेरिका ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 21-20 से मात दी। मिकायला विलियम्स ने विजयी बास्केट किया, जिन्हें टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) चुना गया। यह जीत अमेरिकी महिलाओं के लिए चौथा 3×3 वर्ल्ड कप खिताब था। इससे पहले टीम ने साल 2012, 2014 और 2023 में खिताबी जीत हासिल की थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार महिला फाइनल में पहुंचा था। नीदरलैंड ने अजरबैजान पर 21-14 से जीत के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया।

7 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में दुनियाभर की 40 टीमों ने हिस्सा लिया और 1,00,000 से अधिक दर्शक इसे देखने पहुंचे। शुरुआती टूर्नामेंट, जिसका नाम मूल रूप से फीबा 3×3 वर्ल्ड चैंपियनशिप था, अगस्त 2012 में एथेंस (ग्रीस) में आयोजित किया गया था। पहले संस्करण में एक मिक्स्ड इवेंट था, जिसमें प्रत्येक टीम में 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। अब टूर्नामेंट में सिर्फ दो ही इवेंट होते हैं: एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए।

सर्बिया पुरुषों के मुकाबले में सबसे सफल देश है, जिसने 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं, जबकि अमेरिका 1 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ दूसरे स्थान पर है। लातविया, कतर और ओमान फीबा 3×3 वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाले अन्य देश हैं।

अब तक इस प्रतियोगिता के 10 संस्करण खेले जा चुके हैं। विमेंस फीबा 3×3 वर्ल्ड कप में अमेरिका सबसे सफल देश है। यूएसए ने चार बार खिताब जीता है, जबकि एक बार तीसरा स्थान हासिल किया। फ्रांस, रूस, चीन, नीदरलैंड, चेक गणराज्य और इटली ने भी यह खिताब जीता है।

नेमार इंजरी से रिकवर कर रहे हैं: सीबीएफ

एजेंसी

न्यू जर्सी । ब्राजील के स्टार फॉरवर्ड नेमार की इंजरी फीफा विश्व कप 2026 से पहले टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि, ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (सीबीएफ) ने कहा है कि नेमार इंजरी से रिकवरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसका परिणाम भी दिख रहा है। सीबीएफ ने नेमार के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि स्टार फॉरवर्ड के दाहिने पैर में ग्रेड टू पिंडली की चोट से उनकी रिकवरी का पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन किया गया। 34 साल के नेमार की रिकवरी उम्मीद के मुताबिक है। वह एक खास योजना के तहत इलाज लेते रहेंगे। की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सीबीएफ ने यह नहीं बताया कि वह खेलने के लिए कब तक उपलब्ध होंगे। ' स्थानीय मीडिया के मुताबिक वह कम से कम दूसरे ग्रुप मैच तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। नेमार, ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल किए हैं। इंजरी की वजह से अक्टूबर 2023 के बाद से वह राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेले हैं। हाल में उन्हें अपने क्लब सैंटोस के लिए खेलते हुए मई इंजरी हुई थी। स्टार खिलाड़ी की पिंडली में चोट लगी थी।

ब्राजील अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत शनिवार को मोरक्को के खिलाफ करेगा। इसके बाद उसका सामना हैती और स्कॉटलैंड से होगा। नेमार शुरुआती दो मैचों से बाहर रह सकते हैं। ब्राजील अगले साल रिकॉर्ड 23वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। ब्राजील एकमात्र ऐसी टीम है जिसने विश्व कप के हर एडिशन में हिस्सा लिया है। पूरे करियर में इंजरी की वजह से परेशान रहे 34 साल के नेमार ने संकेत दिया है कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप 2026 उनके करियर का आखिरी विश्व कप होगा।

वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026: मेजबान भारत का स्वर्णिम प्रदर्शन, 102 गोल्ड के साथ 'नंबर-1'

एजेंसी

अहमदाबाद। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने मेडल का शतक लगाते हुए अपने दबदबे को बनाए रखा है। ईकेए एरिना में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 114 मेडल (102 गोल्ड, 9 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज) के साथ प्रतियोगिता का समापन किया। पदक तालिका में जापान 3 गोल्ड और 3 सिल्वर जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, अर्जेंटीना ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिसका श्रेय काफी हद तक उसकी एकमात्र प्रतिनिधि नाबिला बर्राजा को जाता है, जिन्होंने अकेले ही 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीतकर अपनी टीम को टॉप-3 में पहुंचाया। भले ही पदक तालिका में नेपाल पांचवें स्थान पर रहा, लेकिन कुल पदकों की संख्या के लिहाज से

वह भारत के बाद दूसरा सबसे सफल देश साबित हुआ, जिसने कुल 52 मेडल (1 गोल्ड, 36 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज) अपने नाम किए। उज्बेकिस्तान ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए कुल 25 मेडल (1 गोल्ड, 13 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज) जीते।

पहली बार आयोजित इस वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में कुल 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 31 देशों के खिलाड़ियों ने कम से कम एक पदक जीता। इनमें से 10 देशों ने कम से कम एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

मेजबान भारत ने प्रतियोगिता में 122 सदस्यीय दल उतारा था। खिलाड़ियों ने छह आयु वर्गों में प्रतिस्पर्धा की, जिनमें सब-जूनियर पुरुष एवं महिला (10-14 वर्ष), जूनियर पुरुष एवं महिला (14-18 वर्ष), सीनियर (18-28 वर्ष), सीनियर-ए (28-35 वर्ष), सीनियर-बी (35-45 वर्ष) तथा सीनियर-सी (45-55 वर्ष) शामिल थे।

अंडर-18 हॉकी एशिया में पुरुष और महिला टीम ने लहराया तिरंगा, केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया ने सम्मानित किया

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अंडर-18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों को सम्मानित किया। भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मांडविया ने पुरुष टीम को 61.5 लाख रुपए, जबकि महिला टीम को 21 लाख रुपए का चेक सौंपा। काकामिगाहारा में शुक्रवार को खेले गए फाइनल में कप्तान केतन कुशवाहा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से मात देकर खिताब अपने नाम किया। दूसरी तरफ, कप्तान स्वीटी कुजुर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया पर 3-0 की शानदार जीत दर्ज की। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष और महिला दोनों टीमों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, 'देश का नाम रोशन करने के लिए दोनों टीमों ने जो कड़ी मेहनत की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

पूरा देश आप पर गर्व करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह तो बस शुरुआत है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जिसने 13 गोल किए हैं, उसे 15 या उससे अधिक गोल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जिसने 10 गोल रोके हैं, उसे विपक्षी टीम को एक भी गोल न करने देने का लक्ष्य रखना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई करें या खेल, पूरी लगन होनी चाहिए। अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करते रहें और अपने माता-पिता और शुभचिंतकों को खुश करते रहें, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। ' मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित भारत को एक खेल महाशक्ति में बदलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खेल मंत्री ने पुरुष और महिला टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर आशीष तानी पूर्ति और नौशीन नाज और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर आयुष राजक को भी सम्मानित किया, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 10 गोल बचाए। खेल मंत्री ने भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल और सरदार सिंह को भी सम्मानित किया, जो क्रमशः अंडर-18 एशिया कप के लिए भारतीय महिला और पुरुष टीमों के कोच के रूप में कार्यरत हैं।

महिला टी20 विश्व कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वालीं 5 बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय नाम भी शामिल

एजेंसी

नई दिल्ली। महिला टी20 विश्व कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 11 जून से इंग्लैंड की धरती पर इस मेगा इवेंट का आयोजन होना है। आइए आपको उन 5 बल्लेबाजों के नाम बताते हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेली है।

मेग लेनिंगः ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज मेग लेनिंग के नाम महिला टी20 विश्व कप में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। लेनिंग ने साल 2014 में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली थी। उन्होंने महज 67 गेंदों का सामना कररते हुए 126 रन बनाए थे। अपनी इस पारी में लेनिंग ने 18 चौके और 4 छक्के लगाए थे।

डिएंड्रा डॉटिनः वेस्टइंडीज की धाकड़ बल्लेबाज ड्रिएंडा डॉटिन टी20 विश्व कप में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बल्लेबाज रही हैं। उन्होंने 2010 में हुए वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 45 गेंदों में 112 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उन्होंने अपनी इस पारी में 7 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए थे।

हीथर नाइटः महिला टी20 विश्व कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की बल्लेबाज हीथर नाइट का नाम दर्ज है।

महिला टी-20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने घोषित की विश्वस्तरीय कमेंट्री टीम

एजेंसी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला टी-20 विश्व कप के लिए विश्वस्तरीय कमेंट्री टीम की घोषणा कर दी है। इस बार कमेंट्री पैनल में महिलाओं की प्रमुख भूमिका देखने को मिलेगी, जिसमें विश्व कप विजेता खिलाड़ी, पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तान, अनुभवी प्रसारक और क्रिकेट जगत की कई प्रतिष्ठित आवाजें शामिल हैं। महिला टी-20 विश्व कप का आयोजन 12 जून से शुरू होगा, जिसमें उद्घाटन मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर होगा। पूरे टूर्नामेंट के दौरान कुल 33 मुकाबलों का प्रसारण किया जाएगा।

कमेंट्री टीम में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने आईसीसी विश्व कप जीतने का अनुभव हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहीं मेल जोन्स और जूलिया प्राइस इस पैनल में शामिल हैं। वेस्टइंडीज की पूर्व खिलाड़ी स्टेसी-ऐन किंग भी टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने महिला टी-20 विश्व कप जीता था। इंग्लैंड की विश्व कप विजेता टीम की सदस्य रहीं ईसा गुहा और एबोनी रेनफोर्ड-ब्रेंट भी कमेंट्री करेंगी। दोनों वर्ष 2009 में आयोजित पहले महिला टी-20 विश्व कप विजेता इंग्लैंड टीम का हिस्सा भी रही थीं।

पुरुष क्रिकेट से भी कई बड़े नाम इस टीम में शामिल किए गए हैं। दो बार पुरुष विश्व कप जीतने वाले मैथ्यू हेडन, भारत के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक और वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी कार्लोस ब्रैथवेट भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा

क्रिकेट प्रसारण की दुनिया की चर्चित आवाजें नासिर हुसैन, इयान बिशप और इयान स्मिथ भी इस टूर्नामेंट में एक साथ नजर आएँगे। इन तीनों ने वर्ष 2019 पुरुष विश्व कप फाइनल के दौरान भी यादगार कमेंट्री की थी।

कमेंट्री टीम में पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज, ताश फेरेंट, अंजुम चोपड़ा, साइमन डूल, वेदा कृष्णमूर्ति, सना मीर, इसोबेल जॉयस और केटी मार्टिन भी शामिल हैं। प्रस्तुतकर्ताओं और प्रसारण विशेषज्ञों की सूची में चार्ल्स डैगनॉल, नेटली जर्मानोस, एलन विल्किंस, लॉरा मैकगोल्ड्रिक, जतिन सप्रू, कैस नायडू, रौनक कपूर और अली मिशेल जैसे नाम शामिल हैं। इस अवसर पर मेल जोन्स ने कहा कि यह महिला टी-20 विश्व कप अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा और यह महिला क्रिकेट की प्रगति का उत्सव है। मिताली राज ने कहा कि इस बार भाग लेने वाली 12 टीमों में प्रतिभा का स्तर बेहद ऊँचा है और दुनिया को कई यादगार क्षण देखने को मिलेंगे।

ईसा गुहा ने कहा कि मेजबान शहर और मैदान इस बड़े आयोजन को यादगार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। नासिर हुसैन ने कहा कि महिला क्रिकेट के प्रति उत्साह और प्रतिभा का विस्तार पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है और यह टूर्नामेंट भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इयान बिशप ने कहा कि हर आईसीसी आयोजन ऐसी यादें देता है, जो लंबे समय तक लोगों के दिलों में रहती हैं और यह टूर्नामेंट भी वैसी ही नई कहानियाँ लिखेगा।

कच्चे तेल की कीमत से झुलसा शेयर बाजार, बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स-निफ्टी बंद

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव और कच्चे तेल की कीमत में आई तेजी के कारण घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट का शिकार हो गया। आज के कारोबार की शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई थी। हालांकि दिन के पहले सत्र में निचले स्तर पर हुई वैल्यू बाइंग के कारण शेयर बाजार की स्थिति में काफी हद तक सुधार भी हुआ, लेकिन दोपहर एक बजे के करीब बाजार में दोबारा बिकवाली का दबाव बन गया, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की कमजोरी बढ़ती चली गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.97 प्रतिशत और निफ्टी 1.04 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए। आज दिन भर सभी सेक्टर पर दबाव बना रहा। दिन भर हुई बिकवाली के कारण सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। रियल्टी और मेटल सेक्टर के शेयरों में आज जम कर बिकवाली होती रही, जिसके कारण निफ्टी का मेटल इंडेक्स 2.43 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इसी तरह रियल्टी इंडेक्स भी 2.01 प्रतिशत की गिरावट का शिकार हो गया। सके अलावा बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, हेल्थकेयर, ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और टेक इंडेक्स भी गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार बिकवाली होती रही, जिसके कारण निफ्टी का मिडकैप इंडेक्स 1.40 प्रतिशत की गिरावट का शिकार हो गया।

देश में 58 करोड़ जन धन खातों से करोड़ों लोग औपचारिक बैंकिंग से जुड़े : वित्त मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 58 करोड़ से ज्यादा जन धन खातों ने करोड़ों भारतीयों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा। इस विस्तार ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा दिया है। साथ ही सुनिश्चित हुआ है कि कल्याणकारी लाभ और पेंशन बिना किसी लीकेज के सीधे नागरिकों तक पहुंचें। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जन-धन योजना के तहत कल्याणकारी योजनाओं, कम लागत वाले बीमा और पेंशन के लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी और अभाव के खिलाफ लड़ाई में भारत वैश्विक स्तर पर अलग पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त, 2014 को की गई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल में से एक है। इस योजना के तहत 56 फीसदी खाताधारक महिलाएं हैं। वहीं, 67 फीसदी खाते ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जन-धन योजना ने लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में मदद की है, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। मंत्रालय के मुताबिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये लाभार्थियों के खातों में लगभग 45 लाख करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। अब भारत की 94 फीसदी वयस्क आबादी के पास बैंक खाता है।

पूंजी बाजार घरेलू बचत और संपत्ति सृजन का प्रमुख जरिया बन रहे : तुहिन कांत पांडेय

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि भारत में पूंजी बाजार घरेलू बचत और संपत्ति सृजन का प्रमुख माध्यम बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि निवेश के तरीकों में एक संरचनात्मक बदलाव आया है, जिससे लोग तेजी से बाजार आधारित विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। तुहिन कांत पांडेय ने यहां 'आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इंडिया इंवेस्टर कॉन्फ्रेंस 2026' को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि भारत के कैपिटल मार्केट परिवारों की बचत और संपत्ति बनाने का एक अहम जरिया बनते जा रहे हैं। पांडेय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में इक्विटी इश्यू 4.5 लाख करोड़ रुपये और कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू 9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गए हैं। सेबी के चेयरमैन ने कहा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस) के नियमों पर उन्होंने संकेत दिया कि इस पर व्यापक विचार-विमर्श जारी है और जल्द ही एक परामर्श पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कोई समयसीमा बताने से इनकार किया। पांडेय ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति केवल ऊंची वृद्धि दर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण, बचत का वित्तीयकरण और संस्थानों पर बढ़ता भरोसा भी शामिल है।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के लिए ब्याज की दर बढ़ी

नयी दिल्ली। सरकार ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के लिए ब्याज की दर में भारी बढ़ोतरी करते हुए इसे 6.85 प्रतिशत कर दिया है। यह दर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित की गयी है। वित्त मंत्रालय की सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के तहत जमा पर ...01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए 6.85 प्रतिशत ब्याज दर प्रभावी होगी। यह दर 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2024-25 में वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष पर ब्याज दर 3.35 प्रतिशत और 2023-24 में 7.15 प्रतिशत थी। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना वित्त विधेयक 2015 के तहत 18 मार्च 2016 को की गयी थी।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण पर जुलाई तक हो सकता है हस्ताक्षर: पीयूष गोयल

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर जुलाई तक हस्ताक्षर हो सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गोयल ने संकेत दिया कि हाल के टैरिफ संबंधी मुद्दों के बावजूद दोनों देशों के बीच वार्ता अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। मंत्री के इस बयान से उन व्यापार वार्ताओं में जल्द प्रगति की उम्मीद बढ़ गई है, जो पिछले कई महीनों से चल रही हैं। भारत और अमेरिका दोनों आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और कारोबार के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, इससे भारतीय निर्यातकों को कई प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर मिल सकते हैं।

वार्ता की प्रगति पर बात करते हुए गोयल ने कहा कि हाल के सप्ताहों में भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच बातचीत में काफी आगे बढ़त हुई है और अब बचे हुए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री की ताजा टिप्पणी उनके पिछले सप्ताह दिए गए बयान को आगे बढ़ाती है। 5 जून को गोयल ने कहा था कि अमेरिका के विभिन्न व्यापार विभागों के अधिकारियों की एक पूरी टीम नई दिल्ली आई थी और उन्होंने भारतीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की थी ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। गोयल ने कहा था, 'अमेरिका के विभिन्न व्यापार विभागों के अधिकारियों की पूरी टीम दिल्ली में मौजूद थी।'

मंत्री के अनुसार, दोनों पक्ष समझौते में बची हुई खाइयों को पाटने और ऐसा समाधान निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों को समान रूप से लाभ हो।

उन्होंने विश्वास जताया था कि व्यापार समझौते का पहला चरण जुलाई के मध्य तक अंतिम रूप ले सकता है। उन्होंने इसे 'बहुत मजबूत और जीवंत पहला चरण' बताया, जो भविष्य में दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक सहयोग की नींव रखेगा।

यह प्रस्तावित व्यापार समझौता ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब भारत और अमेरिका दोनों आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) में विविधता लाने, निवेश बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं।

यदि यह पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, तो आगे चलकर भारत और अमेरिका के बीच एक अधिक व्यापक और बड़े व्यापार समझौते का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

बीएमडब्ल्यू समूह इंडिया एक जुलाई से वाहन कीमतों में करेगी दो फीसदी तक का इजाफा

एजेंसी

मुंबई। जर्मनी की लग्जरी कार विनिर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू समूह इंडिया अपने सभी बीएमडब्ल्यू और मिनी श्रेणी के वाहनों की कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। नई दरें एक जुलाई से प्रभावी होंगी। यह मूल्य वृद्धि भारत में स्थानीय रूप से विनिर्मित और पूरी तरह आयातित (सीबीयू) दोनों ब्रांड पर लागू होगी बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हरदीप सिंह बरार ने कहा कि वृहद आर्थिक चुनौतियों, खासकर रुपये में गिरावट एवं बढ़ती लॉजिस्टिक लागत के मद्देनजर प्रीमियम मानकों की रक्षा के लिए हम 1 जुलाई से समूचे खंड की कीमतों में दो फीसदी तक की वृद्धि लागू कर रहे हैं। बरार ने कहा कि हमारी मजबूत मांग और बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज की वजह से बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया लग्जरी मोबिलिटी के क्षेत्र में लगातार नए बेंचमार्क सेट कर पा रहा है। बीएमडब्ल्यू इंडिया की स्थानीय रूप से विनिर्मित कारों में 2-सीरीज ग्रैन कूपे, 3-सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस, 5-सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस, 7-सीरीज, एक्स1, एक्स3, एक्स5,

एक्स7, एम340आई और आईएक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी आई5 एम60, आई7, आई7 एम70, बीएमडब्ल्यू आईएक्स एम440आई कन्वर्टिबल, एम2 कूपे, एम4 कॉम्पिटिशन, एम5 और एक्सएम जैसे पूरी तरह आयातित मॉडल भी पेश करती है।

सरकार का दावा- देश में पेट्रोल-डीजल और घरेलू रसोई गैस का पर्याप्त भंडार

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट के बादजूद कच्चे तेल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर बनी हुई है। सरकार ने बताया कि हमारे पास देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव प्रवीण एम. खानूजा ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा हालात के बावजूद कच्चे तेल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर बनी हुई है। घरेलू रिफाइनरियों और फ्रैक्शनटर्स से एलपीजी का घरेलू उत्पादन अधिकतम स्तर पर है। वे रोजाना लगभग 52-53 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) उत्पादन कर रहे हैं, जो संकट से पहले के स्तर से लगभग 60 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर स्टॉक खत्म होने की कोई खबर नहीं है। इसके साथ ही एलपीजी डिलीवरी का बैकलॉग घटकर 4 दिन से भी कम हो गया है, जबकि 99 फीसदी एलपीजी सिलेंडर बुकिंग अब ऑनलाइन होती हैं। वहीं, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) का अनुपालन रेट लगभग 96 फीसदी है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइज़र की खरीद 86.65 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) तक पहुंच गई है, जो कुल जरूरत का 22.57 फीसदी है। उन्होंने कहा कि किसानों ने 11.17 एलएमटी ऑर्गेनिक खाद भी खरीदी है, जबकि पिछले साल इसी समय यह 3.20 एलएमटी थी। इससे पता चलता है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सोर्स की ओर झुकाव बढ़ रहा है। अपर्णा एस. शर्मा ने बताया कि फिलहाल फर्टिलाइजर की उपलब्धता में कोई बड़ी चुनौती नहीं है। घरेलू उत्पादन और आयात जारी है और अब तक 147.40 एलएमटी फर्टिलाइजर का उत्पादन या आयात किया जा चुका है। जून में 25,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आयातित यूरिया, डीएपी और एनपीके फर्टिलाइजर बंदरगाहों पर पहुंचे हैं। इसके अलावा बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज दोपहर करीब 1:30 बजे एमटी मैरीवेक्स जहाज पर आग लगने की घटना की सूचना मिली है। घटना के समय जहाज पर 24 भारतीय नाविक मौजूद थे। सभी भारतीय नाविक अभी सुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम विदेश मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

जी. किशन रेड्डी ने कोयला मंत्रालय की दो वर्षीय उपलब्धियों को रखा सामने, भविष्य की रूपरेखा भी बताई

एजेंसी

हैदराबाद। पश्चिम एशिया के संकट के बीच केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ कोयला गैसीकरण के माध्यम से कोयला भंडार का अधिकतम उपयोग करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में 4 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करके विदेशी मुद्रा में 3 लाख करोड़ रुपये की बचत करना है। हैदराबाद में अपने मंत्रालय के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उपलब्धियों पर मीडिया को किशन रेड्डी ने बताया कि सुधारों के हिस्से के रूप में कोयला गैसीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय 46,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के साथ ठोस कोयले को सिनगैस में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो एक स्वच्छ और बहुमुखी गैसीय ईंधन है। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत के पास जमीन के काफी अंदर कोयले का पर्याप्त भंडार है, लेकिन सरकार पहले चरण में भूमिगत गैसीकरण के बजाय सतही कोयला गैसीकरण को प्राथमिकता दे रही है। इस कार्यक्रम का

उद्देश्य एलएनजी, यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, उर्वरक, अन्य पेट्रोकेमिकल्स और संबंधित उत्पादों जैसे ईंधन और रसायनों के लिए आयात पर निर्भरता कम करना है। राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है पर किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के बाद तीसरा रोडशो अगले सप्ताह मुंबई में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में एक लाख नौकरियां पैदा करने का इरादा रखती है। यह रेखांकित करते हुए कि देश में 72फीसदी बिजली उत्पादन 426 कैप्टिव और कमर्शियल कोयला खदानों से उत्पादित कोयले पर आधारित है, उन्होंने कहा कि भारत ने 2023-24 और 2024-25 दोनों वर्षों में एक बिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है। मानसून के मौसम से पहले, उन्होंने कहा कि भारत के पास 189 मिलियन टन का कोयला भंडार है, जो अगले 85 दिनों की मांग को पूरा करने और निर्बाध बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। यह दावा करते हुए कि सरकार ने कोयला आयात को कम करने का लक्ष्य रखा है, उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में आयात में 4फीसदी की गिरावट आई है।

एसबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार को सौंपा 8,813 करोड़ रुपए का डिविडेंड चेक

एजेंसी

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 8,813 करोड़ रुपए का डिविडेंड (लाभांश) चेक सौंपा।

यह चेक एसबीआई के चेयरमैन सी.एस. शेट्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा। वित्त मंत्री कार्यालय (एफएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को साझा करते हुए बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एसबीआई के चेयरमैन सी.एस. शेट्टी से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,813 करोड़ रुपए का डिविडेंड चेक प्राप्त किया है। यह लाभांश भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र के इस बड़े बैंक के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। साथ ही, यह केंद्र सरकार की गैर-कर (नॉन-टैक्स) आय में एक महत्वपूर्ण योगदान भी माना जा रहा है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब एसबीआई देश के बैंकिंग और डिजिटल भुगतान तंत्र में एक अहम भूमिका निभा रहा है।

सी.एस. शेट्टी के नेतृत्व में एसबीआई लगातार इस बात पर जोर

देता रहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और देश की दीर्घकालिक विकास संभावनाएं बेहतर बनी हुई हैं। इस महीने की शुरुआत में सी.एस. शेट्टी ने कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला आर्थिक परिस्थितियों को संतुलित करने और विकास को समर्थन देने में मदद करेगा।मुंबई में आयोजित एक उद्योग कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि महंगाई की स्थिति नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है, लेकिन मौजूदा समय में ब्याज दरों में कोई बदलाव न करना वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और अर्थव्यवस्था की सुचारु वृद्धि के लिए लाभकारी होगा।

उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर बाजार की उम्मीद है कि इस समय ब्याज दरों में ठहराव आ सकता है। महंगाई की स्थिति महत्वपूर्ण है, लेकिन दरों को स्थिर रखना निश्चित रूप से हालात को संतुलित करने और विकास को सुचारु बनाए रखने में मदद करेगा।' इसके अलावा, देश के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन ने निवेशकों से शेयर बाजार के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से आगे देखने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि निवेशकों को भारत की दीर्घकालिक विकास कहानी पर ध्यान देना चाहिए, जो बैंकिंग सुधारों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे के विकास से संचालित हो रही है। सी.एस. शेट्टी ने कहा, 'सिर्फ सेंसेक्स को मत देखिए, भारत को एक दीर्घकालिक विकास की कहानी के रूप में देखिए।

बेंगलुरु-तुमकुर रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन को मंजूरी, 162.57 करोड़ रुपये खर्च होंगे

एजेंसी

नई दिल्ली । भारतीय रेल ने कर्नाटक के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में शामिल बेंगलुरु-तुमकुर खंड पर रेल क्षमता और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत 120 ट्रैक किलोमीटर (टीकेएम) लंबे रेलखंड पर लागू की जाएगी। रेल मंत्रालय के अनुसार परियोजना के तहत मौजूदा 1×25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को आधुनिक 2×25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में परिवर्तित किया जाएगा। इस परियोजना की स्वीकृत लागत 162.57 करोड़ रुपये है।बेंगलुरु-तुमकुर रेलखंड रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क (एचयूएन) रूट-10 का हिस्सा है, जो पुणे-हुब्बली-चिकजाजुर-बिरूर-तुमकुर-बेंगलुरु-सेलम-कन्याकुमारी रेल कॉरिडोर के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को जोड़ता है। रेलवे के अनुसार, 2×25 केवी सिस्टम अपनाने से ट्रेनों के संचालन के लिए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे इस मार्ग पर अधिक यातायात को कुशलतापूर्वक संभाला जा सकेगा। उन्नत प्रणाली भारी मालगाड़ियों और लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों के संचालन में भी सहायक होगी तथा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाएगी। परियोजना के पूरा होने पर बेंगलुरु महानगर क्षेत्र और आसपास के जिलों को सेवा देने वाले इस महत्वपूर्ण रेल मार्ग पर भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही कर्नाटक और दक्षिण भारत में यात्री तथा माल यातायात की आवाजाही अधिक सुगम और तेज होगी।

असम में ट्राई ने की मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता जांच

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मार्च में असम के लंका से नरैनपुर रेलवे ब्रिज तक एनएच-27 और 627 मार्ग पर मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता की जांच की। इस जांच में कवरेज गैप, कॉल ड्रॉप, कॉल साइलेंस इंस्टेंस और डेटा स्पीड जैसे मानकों का आकलन किया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि एयरटेल और जियो ने औसतन सबसे तेज डाउनलोड स्पीड दर्ज की, जबकि बीएसएनएल और वोडाफोन-आइडिया में कवरेज गैप और कॉल ड्रॉप की समस्या अधिक रही। ट्राई ने बताया कि जांच के दौरान एयरटेल के 23,981 सैंपल में से 4,820, बीएसएनएल के 7,964 सैंपल में से 6,410, जियो के 23,742 सैंपल में से 4,453 और वोडाफोन-आइडिया के 17,252 सैंपल में से 10,218 में कमजोर सिग्नल दर्ज किया गया।

कॉल ड्रॉप दर में एयरटेल के 126 सफल कॉल में से 9, बीएसएनएल के 37 कॉल में से 12, जियो के 128 कॉल में से 14 और वोडाफोन-आइडिया के 95 कॉल में से 21 कॉल ड्रॉप दर्ज हुईं। कॉल साइलेंस इंस्टेंस में एयरटेल में 123 कॉल में से 8 बार, जियो में 97 कॉल में से 6 बार और वोडाफोन-आइडिया में 89 कॉल में से 2 बार खामोशी दर्ज हुई, जबकि बीएसएनएल के आंकड़े उपलब्ध नहीं रहे। डेटा स्पीड में एयरटेल ने औसतन 66.50 एमबीपीएस डाउनलोड और 13.63 एमबीपीएस अपलोड दर्ज किया। जियो ने 88.21 एमबीपीएस डाउनलोड और 6.61 एमबीपीएस अपलोड, वोडाफोन-आइडिया ने 16.84 एमबीपीएस डाउनलोड और 3.99 एमबीपीएस अपलोड तथा बीएसएनएल ने मात्र 4.86 एमबीपीएस डाउनलोड और 3.10 एमबीपीएस अपलोड स्पीड दर्ज की। ट्राई ने बताया कि यह परीक्षण 189.7 किलोमीटर हाईवे ड्राइव और 7 हॉटस्पॉट लोकेशनों पर किया गया। मार्ग में बामुन गांव, डिजाबोरा, मुपा, डिडाओडिप, रेटजोल और दमछरा जैसे स्थान शामिल रहे।

महबूबनगर-सिकंदराबाद-मेडचल रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन को मंजूरी, 285 करोड़ रुपये खर्च होंगे

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय रेल ने दक्षिण मध्य रेलवे के महबूबनगर-सिकंदराबाद-मेडचल रेलखंड पर रेल परिचालन को और अधिक सक्षम एवं आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मौजूदा 1×25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को उन्नत कर आधुनिक 2×25 केवी सिस्टम में अपग्रेड किया जाएगा। रेल मंत्रालय के अनुसार, लगभग 141 रूट किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर यह कार्य 285.01 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यह परियोजना देश के व्यस्त रेल गलियारों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। नई 2×25 केवी सिस्टम लागू होने से ट्रेनों के संचालन के लिए अधिक स्थिर और कुशल बिजली आपूर्ति उपलब्ध होगी, जिससे रेल सेवाएं अधिक सुचारु, सुरक्षित और भरोसेमंद बनेंगी। इससे ट्रेनों के परिचालन में सुधार के साथ-साथ ऊर्जा दक्षता भी बढ़ेगी। महबूबनगर-सिकंदराबाद-मेडचल रेलखंड देश के महत्वपूर्ण हाई डेंसिटी नेटवर्क (एचडीएन) मार्गों में शामिल है। यह धर्मवरम-डोन-महबूबनगर-सिकंदराबाद-मेडचल-मुदखेड़-इंदौर-अजमेर रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जहां यात्री और मालगाड़ियों का भारी आवागमन होता है।परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर माल परिवहन और अधिक प्रभावी होगा, जिससे माल ढुलाई की गति और क्षमता दोनों में वृद्धि होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने कहा कि यह पहल आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप रेल नेटवर्क विकसित करने की उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी तथा बेहतर बुनियादी ढांचे और परिचालन दक्षता के माध्यम से यात्रियों और उद्योग जगत दोनों को लाभ पहुंचाएगी।

एनएलसी इंडिया की तीन प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, खुलेगा ओएफएस

एजेंसी

मुंबई। केंद्र सरकार खनन क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी एनएलसी इंडिया (पूर्व में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन) में अपनी तीन प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचेगी। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि कंपनी का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) मंगलवार 09 जून को संस्थागत एवं बड़े निवेशकों के लिए

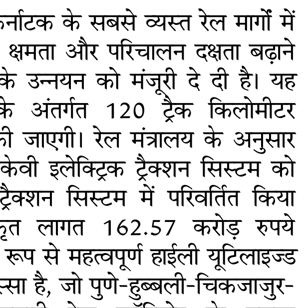

खुलेगा जबकि खुदरा निवेशक 10 जून को बोली लगा सकेंगे। इसके लिए प्रति शेयर न्यूनतम मूल्य 303 रुपये रखा गया है। दीपम ने बताया कि सरकार की योजना दो प्रतिशत शेयरों की बिक्री की है और ज्यादा बोली मिलने की स्थिति में एक प्रतिशत अतिरिक्त शेयरों की बिक्री का प्रावधान रखा गया है। ओएफएस से पहले कंपनी का 10 रुपये अंकित मूल्य वाला इक्विटी शेयर 0.85 रुपये (0.25 प्रतिशत) गिरकर 335.65 रुपये पर बंद हुआ है। कंपनी के पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयरों की संख्या 31 मार्च 2026 को 1,38,66,36,609 थी। इसमें 72.20 प्रतिशत शेयर केंद्र सरकार के पास थे।

दशक भर के आर्थिक सुधारों का नतीजा है 7.7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था: पीयूष गोयल

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की 7.7 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर सरकार द्वारा पिछले एक दशक में किए गए लगातार नीतिगत हस्तक्षेपों और आर्थिक सुधारों का परिणाम है। इन्हीं सुधारों की बदौलत भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। गोयल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि आपमें से किसी ने कल्पना की होगी कि बीता वित्त वर्ष 7.7 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के साथ समाप्त होगा। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक दशक के संरचनात्मक सुधारों का नतीजा है।' मंत्री ने देश भर में निवेश के लिए तैयार 100 औद्योगिक पार्कों के विकास को तेज करने के उद्देश्य से भव्य पोर्टल लॉन्च किया। इससे पहले 23 मई को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे।

इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक छह वर्षों में लगभग 33,660 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय प्रावधान के साथ 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

योजना के पहले चरण में चुनौती-आधारित प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के

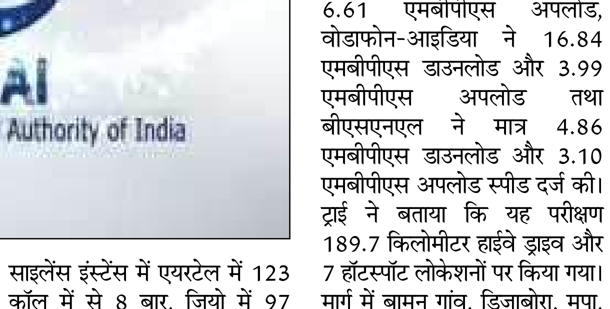

माध्यम से 50 तक औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। 31 जुलाई तक प्राप्त आवेदनों में से 20 औद्योगिक पार्क चुने जाएंगे, जबकि अगले चार महीनों में प्राप्त आवेदनों में से 30 और पार्कों का चयन किया जाएगा। गोयल ने कहा कि सरकार पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। लोगों को बेहतर जीवन स्तर, जीवनयापन में आसानी (ईज ऑफ लीविंग) और कारोबार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है, जिससे देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। मंत्री ने कहा, '25 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। कई पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है। हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो लोगों की बात सुनती है, सतर्क रहती है और समय पर आवश्यक कदम उठाती है।'

गोयल ने कहा कि इस विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारत के निर्यात में पिछले वर्ष भी वृद्धि हुई, जबकि दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के बावजूद भारत के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने यह भी बताया कि भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत ने पिछले वर्ष रिकॉर्ड स्तर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल छह महीनों के भीतर पांच मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को अंतिम रूप दिया है। दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार और निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा, 'भारत केवल अपने विशाल उपभोक्ता बाजार के कारण ही नहीं, बल्कि युवा प्रतिभा और ऊर्जावान जनसंख्या के कारण भी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है।' गोयल ने कहा कि सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वह देश के लोगों के लिए और अधिक काम करने, भविष्य की चुनौतियों के लिए भारत को तैयार करने और विकास की गति को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहरा रही है।

सूडान संकट के समाधान के लिए अमेरिका और सहयोगी देशों ने नागरिक नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया का किया समर्थन

एजेंसी
वॉशिंगटन। अमेरिका और पश्चिमी, अफ्रीकी तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के एक समूह ने सूडान में सूडानी नागरिकों के नेतृत्व में राजनीतिक संवाद शुरू करने का समर्थन किया। उनका कहना है कि केवल नागरिक नेतृत्व वाली सत्ता परिवर्तन प्रक्रिया ही देश में जारी विनाशकारी गृहयुद्ध को समाप्त कर स्थिरता बहाल कर सकती है। सूडान संकट पर अदीस अबाबा में हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य साझेदारों ने कहा कि उनका मानना है कि 'इस संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता' और सूडानी जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। यह बयान 3 से 5 जून के बीच इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित विचार-विमर्श के बाद जारी किया गया। इस बैठक में 'क्विंटेट' समूह के सदस्य शामिल थे, जिनमें अफ्रीकी संघ, इंटरगवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट, लीग ऑफ़ अरब स्टेट्स, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं। इन संगठनों ने सूडान के विभिन्न राजनीतिक पक्षों के साथ चर्चा की।

पीओके के रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को लेकर चिंता, हालात पर उठे सवाल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के रावलकोट क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई कथित गोलीबारी को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'नरसंहार' करार दिया। यूकेपीएनपी के अनुसार, रविवार रात हुई इस घटना में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। संगठन ने कहा कि शांतिपूर्ण और निहत्थे लोगों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पार्टी ने बयान में कहा, 'शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है। पाकिस्तान को निहत्थे कश्मीरियों के खिलाफ अत्याचार और दमन का यह सिलसिला तुरंत बंद करना चाहिए। 'संगठन ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप कर कश्मीरी लोगों के जीवन और उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों से पीओके की जमीनी स्थिति को दुनिया के सामने लाने की अपील की है। रिपोर्टों के अनुसार, रावलकोट इस समय पीओके में फैल रहे विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है। यह विरोध तब तेज हुआ जब प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।

बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष वापस लाने के लिए मंगोलिया पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल

उलानबटार। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल मंगोलिया की राजधानी उलानबटार पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल भगवान बुद्ध के दो मुख्य शिष्यों, अरहंत सारिपुत्र और अरहंत मौद्गल्यायन, के पवित्र अवशेषों को वापस लाने के लिए गया है। मंगोलिया में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, '8 जून को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल, भगवान बुद्ध के दो मुख्य शिष्यों, अरहंत सारिपुत्र और अरहंत मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेषों को भारत वापस ले जाने के लिए एक स्पेशल इंडियन फोर्स फ्लाइट से उलानबटार मंगोलिया पहुंचा।' प्रतिनिधिमंडल का एयरपोर्ट पर मंगोलिया के अरखांगई प्रांत के गवर्नर त्सेरेनदमिद ब्यामबाडू, भारतीय राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे और गंडन मठ के वरिष्ठ भिक्षुओं ने स्वागत किया। इन अवशेषों को 31 मई से 9 जून तक गंडनटेगचेनलिंग मठ में 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए भारत से मंगोलिया लाया गया था। नियम और सुरक्षा के मामले में हेड ऑफ स्टेट का दर्जा पाने वाले अवशेष नई दिल्ली से भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की एक स्पेशल फ्लाइट से उलानबटार पहुंचे, उनके साथ असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था।

हूती विद्रोहियों का तेल अवीव पर मिसाइल हमले का दावा, लाल सागर में इजरायल से जुड़े नेविगेशन पर लगाई रोक

सना। यमन के हूती समूह ने दावा किया कि उसने जाफा इलाके में इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हूती ने लाल सागर में इजरायल से जुड़े समुद्री नेविगेशन पर पूरी तरह से बैन लगाने का ऐलान किया है। सिन्हुआ के अनुसार, समूह के प्रवक्ता याह्या सरिया ने टीवी पर दिए बयान में कहा कि हूती विद्रोहियों ने जाफा में टारगेट पर मिसाइल हमला किया और दावा किया कि ऑपरेशन मकसद में कामयाब रहा। इसके अलावा, सरिया ने लाल सागर में इजरायली समुद्री नेविगेशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया है। हूती प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि इस पानी के रास्ते में चलने वाले इजरायली जहाज को ऐलान के समय से ही एक सही मिलिट्री टारगेट माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हूती विद्रोही अपने सहयोगी समूहों के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ इस ऑपरेशन को और भी तेज कर सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि जब तक यमन और इलाके में उसके सहयोगी समूहों के खिलाफ हमले और नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक हूती अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे।

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने क्यों उठाया पाकिस्तान के 'डीप स्टेट' का मुद्दा? नफरत की फैक्ट्री चलाने का आरोप

एजेंसी
संयुक्त राष्ट्र। पाकिस्तान अपनी डीप स्टेट सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अपने नागरिकों के मन में भारत के प्रति नफरत के बीज बो रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद एक संगठित नफरत की फैक्ट्री चला रहा है, जो धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह कर रहा है। साथ ही सुरक्षा परिषद में आतंकवादी संगठनों का नाम लेकर भारत ने वैश्विक समुदाय पर दबाव बनाने की कोशिश की कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंड न अपनाए जाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा, ''अपनी असफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और दुनिया को गुमराह करने की यह कोशिश असफल साबित होगी।' पी. हरीश ने पाकिस्तान द्वारा अपने देश के भीतर सक्रिय कुछ समूहों को 'फितना अल हिंदुस्तान' कहे जाने की आलोचना करते हुए इसे धार्मिक शब्दावली की आड़ में फैलाया जा रहा सरकारी दुष्प्रचार बताया। 'फितना' एक अरबी धार्मिक शब्द है, जिसका अर्थ 'विद्रोह' या 'मूर्तिपूजा' भी हो सकता है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा, पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा प्रतिष्ठान देश के राजनीतिक और आर्थिक संकटों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी माहौल तैयार करते हैं। हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की 'डीप स्टेट' अपने नागरिकों को लगातार भारत के खिलाफ उकसाकर सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है।उन्होंने 'डीप स्टेट' का उल्लेख पाकिस्तान की सेना की ओर इशारा करते हुए किया, जिसने पिछले साल संवैधानिक संशोधनों के जरिए राजनीति पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उन्होंने कहा, ''27वें संवैधानिक संशोधन के जरिए सेना द्वारा किया गया वास्तविक तख्तापलट इसका सबसे हालिया उदाहरण है।'' यह संशोधन नवंबर में किया गया था, जिसके बाद सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लगभग कानून से ऊपर की स्थिति मिल गई और सरकार पर उनका नियंत्रण और मजबूत हो गया। अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद की चर्चा के दौरान हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सुविधायुक्त आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। अफगानिस्तान पर आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने कहा कि आईएसआईएल (इस्लामिक स्टेट), अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इनके सहयोगी संगठनों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए उस हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें एक पर्यटन स्थल पर 24 हिंदू और एक ईसाई की मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब दक्षिण एशिया में सुरक्षा, आतंकवाद और सीमा-पार गतिविधियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज है।

अमेरिका में खेल कूटनीति और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा, मार्को रुबियो और डाना व्हाइट करेंगे समझौते पर हस्ताक्षर

एजेंसी
वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस हफ्ते यूएफसी के अध्यक्ष और सीईओ डाना व्हाइट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस समझौते का मकसद खेलों के जरिए आपसी संबंधों को बढ़ावा देना और दुनिया भर में मिक्स मार्शल आर्ट्स (एमएमए) के खेल को और फैलाना है। हस्ताक्षर समारोह 11 जून को अमेरिकी विदेश विभाग में आयोजित होगा। अधिकारियों के अनुसार, यह अमेरिकी सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स संस्था अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (यूएफसी) के बीच एक नई सार्वजनिक-निजी साझेदारी की शुरुआत होगी। विदेश विभाग के अनुसार, इस समझौते का उद्देश्य 'खेल कूटनीति से जुड़ी पहलों को मजबूत करना और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के वैश्विक विकास में सहयोग करना' है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। इसके कारण मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते खेलों में शामिल हो गया है। विदेश विभाग ने कहा कि इस साझेदारी से जुड़ी अधिक जानकारी समारोह के बाद जारी की जाएगी।यह समझौता इस बात का संकेत है कि अमेरिका खेलों को सार्वजनिक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के एक माध्यम के रूप में अधिक महत्व दे रहा है। लंबे समय से खेल आदान-प्रदान कार्यक्रम अमेरिकी कूटनीति का हिस्सा रहे हैं।

ट्रंप का दावा- ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार

एजेंसी
वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश छोड़ने और अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य अभियानों ने तेहरान की सैन्य क्षमताओं को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। मंगलवार को होने वाली रिपब्लिकन प्राइमरी से पहले साउथ कैरोलिना के सीनेटर लिंडसे ग्राहम के लिए एक वर्चुअल टेली-रैली में बोलते हुए, ट्रंप ने अपनी ज्यादातर बातें ईरान, चल रही बातचीत और मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति पर केंद्रित कीं। ट्रंप ने कहा, 'हम अभी बातचीत कर रहे हैं और वे एक बहुत अच्छी डील करना चाहते हैं। वे हमें सब कुछ देने को तैयार हैं। वे हमें कोई भी परमाणु हथियार न रखने का वादा करने को भी तैयार हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते और यह बात बहुत स्पष्ट है। '

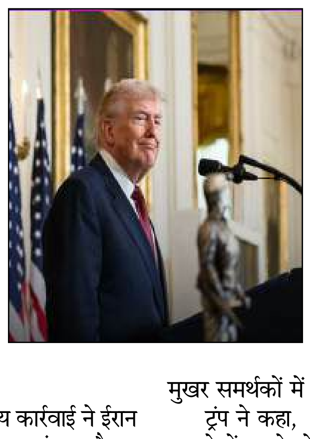

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने कहा, 'हमने उनकी सेना को तबाह कर दिया है। हमने उनकी हर उस चीज को तबाह कर दिया है जिसे तबाह किया जा सकता था, जिसमें उनका नेतृत्व भी शामिल है। उनकी नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उनके पास 159 जहाज थे। हर जहाज अभी पानी के नीचे है। '

राष्ट्रपति ने बातचीत से अच्छे नतीजे की उम्मीद जताई और कहा कि जल्द ही जीत की औपचारिक घोषणा हो सकती है।

ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम वह लड़ाई जीत रहे हैं, लेकिन आप असल में इसे अगले दो सप्ताह में जीतेंगे जब हम पूरी जीत का ऐलान करेंगे। यह पूरी जीत होगी। यह बहुत जल्द होगा और तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। '

ये बातें तब कहीं गईं जब ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में रिपब्लिकन वोटरों से ग्राहम का समर्थन करने को कहा। ग्राहम उनके लंबे समय से सहयोगी रहे हैं और ईरान के प्रति सख्त रुख अपनाने के मामले में सीनेट में सबसे मुखर समर्थकों में से एक रहे हैं।

ट्रंप ने कहा, 'और लिंडसे शुरू से ही मेरे साथ इस मामले में लड़ते रहे हैं। हम एक बहुत मजबूत टीम रहे हैं। ' ट्रंप ने बॉर्डर सिक्योरिटी, मिलिट्री खर्च और कंजर्वेटिव ज्यूडिशियल नियुक्तियों में ग्राहम की भूमिका की भी तारीफ की।

होर्मुज में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट सुरक्षित : ट्रंप

एजेंसी
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक अमेरिकी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। रॉयटर्स के अनुसार, वाशिंगटन डीसी लौटने से पहले जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, 'पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन जारी करेगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना कह सकता हूं कि दोनों पायलट ठीक हैं।' इससे पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिकी सेना का एक अपाचे गनशिप हेलीकॉप्टर होर्मुज के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, हेलीकॉप्टर के गिरने के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना के बाद दोनों पायलटों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया और वे सुरक्षित हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने फिलहाल घटना के कारणों पर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है।

इसके साथ ही ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायल और ईरान फिलहाल तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं और अगले एक सप्ताह तक एक-दूसरे के खिलाफ कोई नई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद ये बयान दिया।

पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, 'नेतन्याहू के साथ बेहद सकारात्मक चर्चा हुई। हालिया घटनाक्रम में इजरायल पर हमला हुआ था, जिसके जवाब में उसने भी कार्रवाई की। दोनों पक्ष अब फिलहाल संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और कुछ समय के लिए एक-दूसरे को छोड़ देने पर सहमत हुए हैं। ' ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि 'अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है।' उनके मुताबिक यह समझौता ऐसा होगा जो किसी भी रूप में ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो से तीन दिनों में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। राष्ट्रपति ने होर्मुज का भी जिक्र किया और कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पूरी तरह खुल जाएगा। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए अपनाई गई अमेरिकी रणनीति का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य हमलों की तुलना में आर्थिक नाकेबंदी अधिक प्रभावी साबित हुई है। उन्होंने कहा, 'अगर अमेरिका चाहे तो बड़े पैमाने पर बमबारी कर सकता है, लेकिन इससे भारी जान-माल का नुकसान होगा और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। '

उनके अनुसार, बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। यही वजह है कि तेहरान अब समझौते की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार दिखाई दे रहा है।

उत्तर कोरिया और चीन ने दोस्ती के नए दौर में किया प्रवेश, परमाणु कार्यक्रम पर नहीं हुई बात

एजेंसी
प्योंगयांग। उत्तर कोरिया और चीन ने अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। दोनों ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह सहमति उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्योंगयांग में हुई शिखर वार्ता के दौरान बनी। दोनों के बीच प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बात नहीं हुई। हालांकि, जिनपिंग की यात्रा से पहले किम जो योंग ने कहा था कि किसी भी कीमत पर न तो उनका देश अपने परमाणु संपन्न दर्जे को छोड़ेगा और न ही किसी की धमकी बर्दाश्त करेगा। सात वर्षों बाद उत्तर कोरिया की अपनी पहली राजकीय यात्रा (8-9 जून) पर पहुंचे शी जिनपिंग का प्योंगयांग में भव्य स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया अध्याय बताया और कहा कि भविष्य में उच्चस्तरीय संपर्क और रणनीतिक संवाद को और मजबूत किया

जाएगा। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए के हवाले से योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि, दोनों देशों ने एक-दूसरे की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों का समर्थन जारी रखने का भी वादा किया। किम जोंग उन ने चीन के साथ संबंधों को अपने देश की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि प्योंगयांग और बीजिंग के रिश्तों को समाजवादी देशों के बीच सहयोग का आदर्श मॉडल बनाया जाएगा। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब उत्तर कोरिया और चीन अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के वर्षों में रूस के साथ उत्तर कोरिया की बढ़ती नजदीकियों के कारण दोनों देशों के संबंधों में कुछ ठंडापन देखा गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि शी चिनफिंग की यह यात्रा उत्तर कोरिया पर चीन के प्रभाव को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।किम ने शी के इस फैसले की भी सराहना की कि उन्होंने वर्ष 2026 की अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए प्योंगयांग को चुना। उनके अनुसार, 'यह कदम दोनों देशों की मित्रता के प्रति चीन की प्राथमिकता और उत्तर कोरियाई जनता के प्रति समर्थन को दर्शाता है। ' जिनपिंग ने भरोसा दिलाया, 'अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, बीजिंग दोनों देशों के साझा हितों की रक्षा करने और अनुकूल रणनीतिक माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। ' रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों ने उच्चस्तरीय दौरों और नियमित संवाद के जरिए आपसी संपर्क को और मजबूत करने पर सहमति जताई।

10 भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को 2026 किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में मिली पहचान

एजेंसी
कैनबरा। 2026 किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में 10 भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को शामिल किया गया है। इन लोगों को ऑस्ट्रेलियाई समाज में उनकी खास सेवा और योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है।

2026 किंग्स ऑनर्स लिस्ट में सामुदायिक सेवा, चिकित्सा, विज्ञान, शिक्षा, लोक प्रशासन, रक्षा, खेल और कला में शानदार सेवा और उपलब्धि के लिए 948 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को शामिल किया गया है। लिस्ट में कई जाने-माने भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई लोगों को 'मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया' (ओएएम) और उससे भी बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो ऑस्ट्रेलियाई समाज में भारतीय समुदाय के बढ़ते योगदान को दिखाता है। 'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में शामिल भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों में प्रोफेसर वलसम्मा इपेन (एओ), डॉ. अभिषेक कुमार वर्मा (ओएएम), डॉ. दिलीप कुमार गहनकारी (ओएएम), प्रोफेसर बालासुब्रमण्यम वेंकटेश (एएम), नोशिर ईरानी (ओएएम), चेथिकाड ओमन थॉमस (ओएएम), उषा किरण चंद्रा (ओएएम), डॉ. अतुल कुमार गर्ग (ओएएम), सौरभ मिश्रा (ओएएम) और बिजिंदर दुगल (ओएएम) शामिल हैं।

इन्हें को चिकित्सा, मनोचिकित्सा, समुदाय नेतृत्व, व्यापार, बुजुर्गों की देखभाल और बहुसांस्कृतिक जुड़ाव में उनकी शानदार सेवा के लिए सम्मानित किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोग ने भारतीय मूल के उन 10 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को बधाई दी, जिन्हें 2026 किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में शामिल किया गया है।

भारतवंशी नित्या रमन ने लॉस एंजिल्स मेयर पद की दौड़ में शामिल, समर्थकों का जताया आभार

एजेंसी
लॉस एंजिल्स। भारतवंशी नित्या रमन ने लॉस एंजिल्स के मेयर पद की दौड़ में एक महत्वपूर्ण जीत (प्राइमरी चुनाव) हासिल करते हुए नवंबर में होने वाले आम चुनाव के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने अमेरिका की मशहूर शख्सियत को मात दी। नित्या ने पूर्व रियलिटी टीवी स्टार स्पेंसर प्रैट को हराकर चुनाव के अगले चरण में प्रवेश किया है। अब उनका मुकाबला मौजूदा मेयर करेन बैस से होगा। अपनी जीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नित्या रमन ने मतदाताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'यह सफलता केवल उनकी नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जिन्होंने घर-घर जाकर प्रचार किया, फोन कॉल किए, संदेश भेजे, दान दिया और

उनके अभियान को मजबूत बनाने में योगदान दिया।' रमन ने अपने संदेश में शहर के सामने मौजूद चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से शहर की राजनीति में प्रभावशाली हित समूहों को प्राथमिकता दी जाती रही है, जबकि आम नागरिक बढ़ते किराए, कमजोर सार्वजनिक सेवाओं और कई अन्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि वे एक ऐसा लॉस एंजिल्स बनाने के लिए काम करेंगी जो सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित, किफायती और बेहतर हो।

नित्या रमन का राजनीतिक सफर सामाजिक कार्यों से शुरू हुआ था। सिटी काउंसिल में चुने जाने से पहले वह बेघरों के मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करती थीं। उनका लक्ष्य शहर में बेघर लोगों की संख्या कम करना और 2028 ओलंपिक खेलों से पहले सड़कों और अस्थायी शिविरों में रहने वाले लोगों की स्थिति में बड़ा सुधार लाना है।

एक शहरी योजनाकार के रूप में प्रशिक्षित रमन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और एमआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है। वर्ष 2020 में उन्होंने लॉस एंजिल्स सिटी काउंसिल का चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली एशियाई-अमेरिकी महिला और पहली दक्षिण एशियाई बनी थीं। मार्च 2024 में उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए भी भारी समर्थन मिला। अपने कार्यकाल के दौरान रमन ने बेघरों के लिए सेवाओं का विस्तार, किफायती आवास निर्माण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है। अब उनकी नजर मेयर पद की जीत पर है।

एच-1बी वीजा शुल्क पर व्हाइट हाउस ने किया ट्रंप का बचाव, अमेरिकी अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी

एजेंसी
वाशिंगटन। अमेरिकी अदालत से 1 लाख डॉलर का एच-1बी वीजा शुल्क रद्द होने के बाद व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बचाव किया है। अमेरिकी संघीय अदालत ने वीजा शुल्क को यह करते हुए रद्द कर दिया कि प्रशासन ने अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर काम किया और एक गैर-कानूनी टैक्स लगाया। अदालत के फैसले के बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने आईएएनएस से कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के पास किसी भी श्रेणी के विदेशियों के प्रवेश को रोकने का स्पष्ट कानूनी अधिकार है, जिन्हें वे अमेरिका के सर्वोत्तम हित में नहीं मानते हैं और उन्होंने ठीक यही किया।' एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'एच-1बी प्रोग्राम का दशकों से दुरुपयोग हो रहा था और राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार इसे ठीक करने के लिए कदम उठाया। वाशिंगटन में एक फेडरल जज पहले ही लगभग ऐसे ही एक आदेश को सही ठहरा चुके हैं और प्रशासन को भरोसा है कि अपील करने पर यह आदेश पलट दिया जाएगा। '

व्हाइट हाउस ने यह नहीं बताया कि वह कब अपील करेगा। हालांकि, प्रशासन के अधिकारियों ने संकेत दिया कि वे इस उपाय का बचाव करना जारी रखेंगे, क्योंकि यह एच-1बी प्रोग्राम पर निगरानी कड़ी करने की राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। यह प्रतिक्रिया कुछ घंटों बाद आई, जब मैसाचुसेट्स के अमेरिकी जिला न्यायाधीश लियो टी. सोरोकिन ने इस नीति को अमान्य कर दिया और इसे पूरे देश में रद्द कर दिया। अपने कड़े शब्दों वाले फैसले में सोरोकिन ने निष्कर्ष निकाला कि प्रशासन ने कांग्रेस की अनुमति के बिना टैक्स लगाया।

जज ने अपने फैसले में लिखा, 'अदालत का मानना है कि यह पॉलिसी कांग्रेस की ओर से जरूरी अधिकार दिए बिना एच-1बी याचिकाओं पर टैक्स लगाती है। ऐसी कोई विधायी शक्तियां नहीं हैं जो प्रतिवादियों को एच-1बी याचिकाओं पर एक लाख डॉलर शुल्क लागू करने का अधिकार देती हों। ' अदालत ने प्रशासन की इस दलील को खारिज कर दिया कि इमिग्रेशन कानून के तहत राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियां इस फीस की अनुमति देती हैं। जज ने कहा कि प्रशासन की ओर से बताए गए इमिग्रेशन कानून राष्ट्रपति को ऐसा शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देते हैं।

यूएफसी का व्हाइट हाउस में डेब्यू, ट्रंप के नेतृत्व में सजेगा फ्रीडम 250 का मंच

एजेंसी
वॉशिंगटन। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (यूएफसी) व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अपना पहला इवेंट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच, अमेरिकी विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) द्वारा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की इस दिग्गज कंपनी के साथ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी साझेदारी शुरू करने का फैसला यह दिखाता है कि यह संगठन खेल, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में कितनी बड़ी ताकत बन गया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो, यूएफसी के प्रेसिडेंट और सीईओ डाना व्हाइट के साथ 11 जून को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। यह कार्यक्रम अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न के तहत 14 जून को व्हाइट हाउस में होने वाले 'यूएफसी फ्रीडम 250' से कुछ दिन पहले आयोजित होगा। इसे व्हाइट हाउस में आयोजित होने वाला पहला यूएफसी फाइट कार्ड बताया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार, इस ऐतिहासिक फाइट नाइट में इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेथजे के बीच चैंपियनशिप का मुख्य मुकाबला होगा, जबकि व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में होने वाले को-मेन इवेंट में एलेक्स परेरा का सामना सिरिल गेन से होगा। यूएफसी की प्रचार सामग्री में इस कार्यक्रम को अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न के दौरान आयोजित होने वाला विशेष आयोजन बताया गया है।

डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज ने महंगाई और ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा

एजेंसी
वॉशिंगटन। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका में जीवन यापन की लागत बढ़ा रहा है, हेल्थकेयर का प्रभावी प्रबंधन नहीं कर रहा है और अमेरिका को ईरान के साथ एक ऐसी लापरवाही भरी और महंगी जंग की ओर धकेल रहा है, जिसे टाला जा सकता था। कैपिटल हिल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेफरीज ने कहा कि जब हाउस डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन बजट रिकॉन्सिलिएशन पैकेज का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं, तब उनके लिए 'किफायती जीवन' (अफोर्डेबिलिटी) सबसे अहम मुद्दा बना रहेगा। जेफरीज ने कहा, 'इस कांग्रेस की शुरुआत से ही हाउस डेमोक्रेट्स ने स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका में जीवन-यापन की लागत बहुत अधिक है और डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वह पहले ही दिन से खर्च कम करेंगे। लेकिन खर्च कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है। ' उन्होंने किराने का सामान, घर, हेल्थकेयर और यूटिलिटी (बिजली-पानी आदि) की बढ़ती कीमतों का ज़िक्र करते हुए कहा कि कई कामकाजी परिवारों के लिए 'अमेरिका बहुत महंगा हो गया है '।

जेफरीज ने घरेलू खर्च बढ़ने के लिए ट्रंप की टैरिफ नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया और रिपब्लिकन हेल्थकेयर नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इनकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस की लागत बढ़ गई है।

उन्होंने कहा, 'ट्रंप के टैरिफ की वजह से आम अमेरिकियों का सालाना खर्च हजारों डॉलर बढ़ गया है। ईरान में अपनी मर्जी से शुरू की गई डोनाल्ड ट्रंप की गैर-जिम्मेदाराना और महंगी जंग की वजह से गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। '

डेमोक्रेटिक नेता ने कहा कि हाउस डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन रिकॉन्सिलिएशन बिल का 'पूरी तरह से विरोध' करेंगे। उन्होंने कहा कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल लागत कम करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को '70 अरब डॉलर का एक और ब्लैंक चेक' देने के लिए। जेफरीज ने बिल पुल्टे को नेशनल इंटेलिजेंस का एक्टिंग डायरेक्टर बनाने के ट्रंप के फैसले की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने पुल्टे को 'एक राजनीतिक चमचा, एक बुरा मजाकिया आदमी' कहा और कहा कि 'वे फ़ेडरल सरकार में किसी भी पद पर काम करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं। '

जब उनसे पूछा गया कि अगर पुल्टे इस पद पर बने रहते हैं तो क्या डेमोक्रेट्स विदेशी निगरानी से जुड़े अहम अधिकारों को बढ़ाने का समर्थन कर सकते हैं, तो जेफरीज ने एक शब्द में जवाब दिया, 'नहीं। '

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जेफरीज ने बार-बार कहा कि रिपब्लिकन वोटरों की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने हाउस रिपब्लिकन पर आरोप लगाया कि वे 'डोनाल्ड ट्रंप के चरम एजेंडे के लिए बस लापरवाह रबर स्टैम्प' हैं और भविष्यवाणी की कि वे 'नवंबर में अपना बहुमत खोने की कगार पर हैं। ' जेफरीज ने कहा कि भविष्य का डेमोक्रेटिक शासन एजेंडा किफायती जीवन और हेल्थकेयर पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा, 'यह जीवन यापन की बढ़ती लागत को कम करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करेगा और निश्चित रूप से इसके हिस्से के तौर पर हमारे खराब हेल्थकेयर सिस्टम को ठीक करने पर भी। ' जेफरीज ने न्यूयॉर्क निक्स के एक मैच में ट्रंप के संभावित शामिल होने की चर्चा को भी खारिज किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप निक्स के इतने बड़े प्रशंसक हैं।' उन्होंने संकेत दिया कि राष्ट्रपति एनबीए फाइनल के साथ खुद को जोड़कर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे।

page 1 and 8 June 10_page 1 Mar 25 final ds.qxd 09-Jun-26 11:54 PM Page 2

स्थानीय समाचार

सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर अमित शाह ने मोदी सरकार की जनकल्याण और विकास उपलब्धियों की सराहना की

नई दिल्ली, 9 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह* ने सरकार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि देश ने पहली बार गरीब कल्याण और अभूतपूर्व विकास को एक साथ साकार होते देखा है।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 वर्षों में बिना थके राष्ट्र और उसके नागरिकों की सेवा की है तथा उनके नेतृत्व में अनेक जनकल्याणकारी और आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

उन्होंने कहा,卐मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान देश ने पहली बार गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास को समानांतर रूप से साकार होते देखा है।

गृह मंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया, चार करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए गए, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया तथा 10 करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए।

उन्होंने यह भी बताया कि इस अवधि में 90 से अधिक नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ, 140 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की गई, 1.45 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और 3,000 किलोमीटर आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए गए।

भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है।

उन्होंने कहा,मोदी जी ने इन 12 वर्षों के दौरान एक भी दिन का अवकाश लिए बिना देश और देशवासियों की निरंतर सेवा की है।

शाह ने कहा कि ऐसा परिवर्तन तभी संभव है जब नेतृत्व की नीयत साफ हो, लक्ष्य राष्ट्रहित में हों और समर्पण पूर्ण हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार तथा 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी।

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी से जुड़े आतंक-गैंगस्टर नेटवर्क मामलों में एनआईए की पंजाब और हरियाणा में छापेमारी

नई दिल्ली, 9 जून। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शहजाद भट्टीसे जुड़े तीन आतंक-गैंगस्टर नेटवर्क मामलों की जांच के तहत पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर छापेमारी की।

एनआईए की टीमों ने दोनों राज्यों के नौ जिलों में कुल 18 स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया और मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए कई लोगों से पूछताछ की।

जांच एजेंसी द्वारा जारी बयान के अनुसार, तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज तथा विभिन्न संचार नेटवर्क, वित्तीय लेन-देन और एजेंसी की निगरानी में मौजूद व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी जब्त की गई।

एनआईए ने कहा कि तलाशी के दौरान एकत्रित सभी सूचनाओं और साक्ष्यों को जांच, फॉरेंसिक परीक्षण तथा तकनीकी विश्लेषण के लिए भेजा गया है, ताकि इस सीमा-पार साजिश के व्यापक नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

बयान में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों को आगे की पूछताछ के लिए जांच में शामिल होने के नोटिस भी जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई सीमा पार से गैंगस्टर से आतंकवादी बने शहजाद भट्टी द्वारा संचालित नेटवर्क के पीछे की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से की जा रही है।

एनआईए ने बताया,आज की छापेमारी का मुख्य उद्देश्य भट्टी के सहयोगियों और तीनों मामलों से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करना था।

जांच के दौरान एनआईए ने पाया है कि मार्च 2025 में पंजाब के जालंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर **रोजर संधूके घर पर हुए ग्रेनेड हमले के पीछे शहजाद भट्टी का हाथ था।

अप्रैल 2026 में एनआईए ने इस मामले में फरार आरोपी शहजाद भट्टी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने यह भी पाया कि नवंबर 2025 में हरियाणा के सिरसा महिला पुलिस थाने में हुए विस्फोट और जनवरी 2026 में हरियाणा के अंबाला स्थित बलदेव नगर पुलिस थाने में हुए धमाके की साजिश भी भट्टी ने रची थी।

डिजिटल समृद्धि का नया आधार बनेगा प्रोजेक्ट गंगा : मुख्यमंत्री

▶▶ गांव-गांव तक हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने किया प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ

▶▶ 20 लाख परिवारों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बड़ी पहल,एक लाख से अधिक रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

▶▶ 57 हजार ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा प्रोजेक्ट गंगा का नेटवर्क

***लखनऊ, 09 जून।** उत्तर प्रदेश के गांवों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने, डिजिटल समावेशन को नई गति देने और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, कौशल विकास और तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसरों का विस्तार करेगी।

प्रोजेक्ट गंगा के तहत प्रदेश में डिजिटल सेवा प्रदाताओं (डीएसपी) का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से लगभग 20 लाख परिवारों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने, 8 से 10 हजार डिजिटल सेवा प्रदाता तैयार करने तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के प्रथम चरण में 21 जनपदों में इसका संचालन प्रारंभ किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के दौर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एक बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट की गति जितनी तेज होगी, विकास की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट गंगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार गंगोत्री से गंगासागर तक मां गंगा का प्रवाह अपने मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के विकास, समृद्धि और जीवन का आधार रहा है, उसी प्रकार प्रोजेक्ट गंगा भी उत्तर प्रदेश की डिजिटल समृद्धि का एक मजबूत आधार बनेगा। यह पहल गांवों तक डिजिटल अवसर पहुंचाकर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की नई संभावनाएं सृजित करेगी।उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में ई-ऑफिस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), बीसी सखी, ग्राम सचिवालय सहित अनेक तकनीक आधारित पहलों के माध्यम से शासन और जनता के बीच की दूरी कम हुई है। इन प्रयासों ने डिजिटल सशक्तिकरण को नई गति दी है और आम नागरिकों तक सेवाओं की पहुंच को आसान बनाया है। प्रोजेक्ट गंगा इसी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण चरण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में 21 जनपदों में प्रारंभ हो रही इस परियोजना को आगे चलकर प्रदेश की सभी 57 हजार ग्राम पंचायतों और लगभग 8 हजार न्याय पंचायतों तक पहुंचाना होगा। इससे लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी की परिकल्पना साकार होगी और गांव स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित होंगे।

राणा ने फट्टू कोटली में 2.47 करोड़ के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का शिलान्यास किया, भगतपुर में तवी तटबंध का निरीक्षण

जम्मू, 9 जून। जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राना ने आज गारखाल क्षेत्र के फट्टू कोटली में चिनाब नदी के बाएं किनारे पर 2.47 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ सुरक्षा कार्यों के पुनर्निर्माण एवं संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर अखनूर के विधायक मोहन लाल भगत और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह परियोजना बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि नदी किनारों पर मजबूत संरचनाएं बनाकर लोगों की जान-माल और कृषि भूमि की रक्षा करना जरूरी है।

उन्होंने निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी बाढ़ सुरक्षा कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। इसके बाद मंत्री ने जम्मू जिले के मरह ब्लॉक के भगतपुर गांव में तवी नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से पुनर्स्थापन योजना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और समयबद्ध समाधान का आश्वासन दिया।

कुपवाड़ा के अल्लाचिजाब गांव का निदेशक रेशम विभाग का दौरा

कुपवाड़ा, 9 जून। रेशम विभाग कश्मीर के निदेशक एजाज अहमद भट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अल्लाचिजाब गांव का दौरा किया और विकास कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने पंचायत घर में अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया।

ग्रामीणों ने स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल और सड़क जैसी समस्याएं उठाईं। निदेशक ने आश्वासन दिया कि सभी उचित मांगों का समाधान समय पर किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आय बढ़ाने की अपील भी की।

जोजीला सुरंग के ऐतिहासिक निर्माण को उपराज्यपाल सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक परिवर्तनकारी कदम बताया

लेह, 09 जून (हि.स.)। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को जोजीला सुरंग के ऐतिहासिक निर्माण को केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक परिवर्तनकारी कदम बताया।

उन्होंने कहा कि इससे संपर्क में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्वप्निल पहल बताते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि यह सुरंग लद्दाख और शेष भारत के बीच साल भर संपर्क प्रदान करेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार लाएगी।

सक्सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री की स्वप्निल परियोजना जोजीला सुरंग का ऐतिहासिक निर्माण लद्दाख के विकास की राह में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। इससे लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क काफी मजबूत होगा और शेष भारत के साथ साल भर संपर्क बना रहेगा।केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा साझा की गई एक पोस्ट का जवाब देते हुए जिसमें उन्होंने इस निर्माण को भारत के अवसंरचना विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क बनाए रखने वाला बताया था, उपराज्यपाल ने परियोजना को संभव बनाने और लद्दाख को महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में सहयोग देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सक्सेना ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे और लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सतत विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

ओमान तट के पास मिसाइल हमले में टैंकर से 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित बचाए गए

नई दिल्ली, 9 जून। ओमान के तट के पास एक व्यापारी टैंकर पर हुए मिसाइल हमले के बाद उसमें सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह बचाव अभियान भारतीय और ओमान समुद्री अधिकारियों के बीच त्वरित समन्वय के बाद सफल हुआ।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) मुंबई को सोमवार दोपहर लगभग 2-20 बजे सूचना मिली कि ओमान के मसीरा के पास पालाउ ध्वज वाले टैंकर एमटी मैरिवेक्स पर मिसाइल हमला हुआ है। इस जहाज पर सवार सभी 24 चालक दल के सदस्य भारतीय नागरिक थे।

यह अलर्ट एमआरसीसी मुंबई को जहाज पर मौजूद एक चालक दल के सदस्य के रिश्तेदार द्वारा दिया गया। स्थिति की गंभीरता और चालक दल पर तत्काल खतरे को देखते हुए एमआरसीसी मुंबई ने तुरंत ओमान समुद्री खोज और बचाव केंद्र (ओएमएससी) से संपर्क किया और आपातकालीन सहायता का अनुरोध किया।

ओएमएससी ओमान ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया, जिसमें पास के एक जहाज को मोड़ा गया और दो ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर भेजे गए।

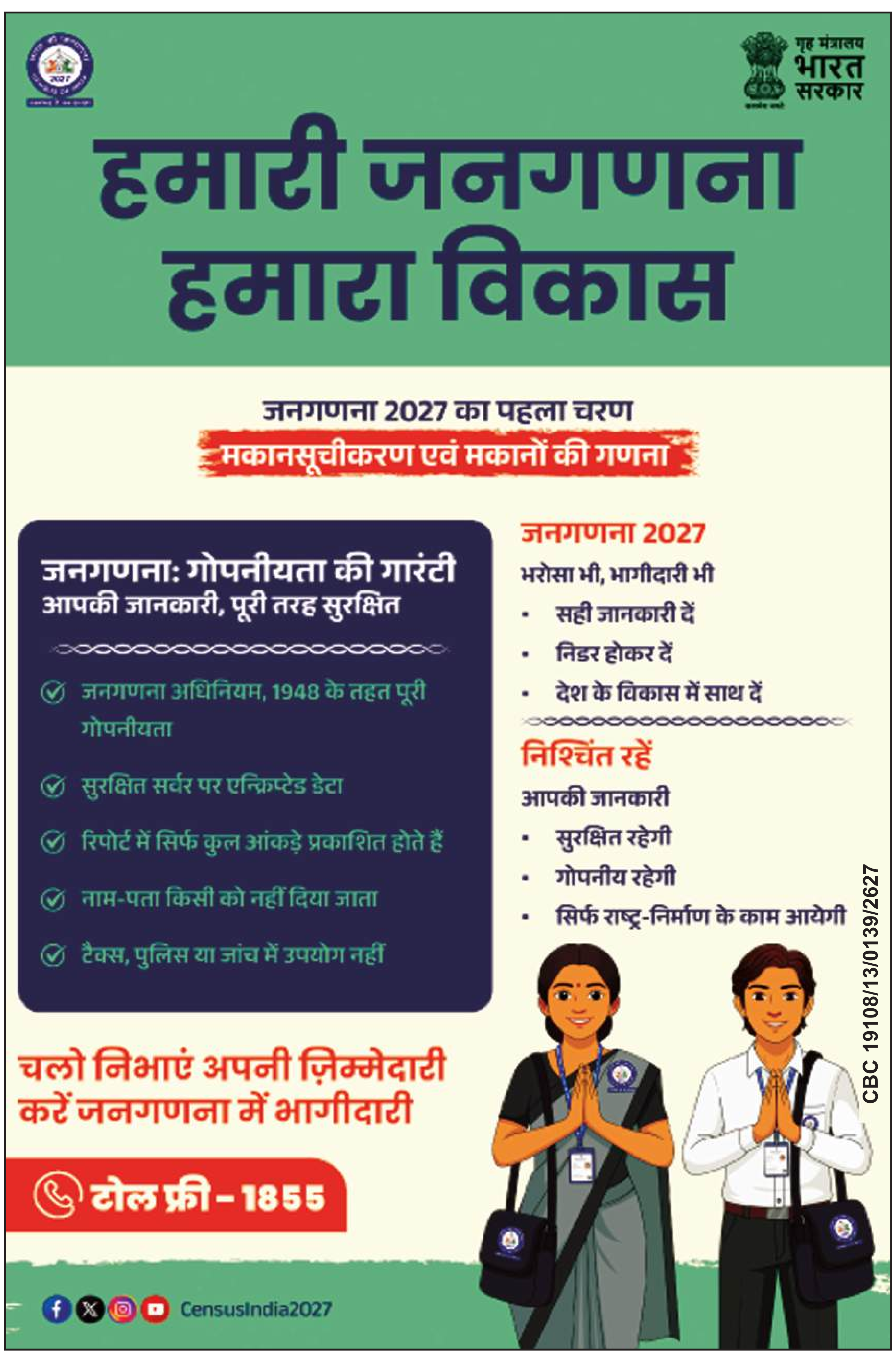

सकीना इत्तू ने मुहर्रम के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की

श्रीनगर, 9 जून। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने आगामी मुहर्रम-उल-हराम के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने हेतु एक विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने निर्देश दिए कि जुलूसों और धार्मिक सभाओं के दौरान हर प्रमुख स्थान पर चिकित्सा शिविर, आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहें।

उन्होंने एसकेआईएमएस, जेवीसी अस्पताल, एसएमएचएस सहित सभी प्रमुख अस्पतालों को मेडिकल कैंप स्थापित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस सेवाएं चौबीसों घंटे सक्रिय रहें और किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तैयारी रखी जाए। उन्होंने अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

जोज़िला सुरंग के ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू पर उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार जताया

श्रीनगर, 9 जून। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज ऐतिहासिक जोज़िला सुरंग के ब्रेकथ्रू को वास्तविकता बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए कनेक्टिविटी और विकास के नए युग की शुरुआत करेगी। एशिया की सबसे लंबी द्विदिशीय सुरंग कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच सालभर संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

उपराज्यपाल ने कहा कि यह इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना यात्रा समय को कम करेगा, यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाएगा और ईंधन की बड़ी बचत सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में यह सुरंग इस क्षेत्र के लिए जीवनरेखा साबित होगी, जो सप्लाई चेन को मजबूत करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी और सशस्त्र बलों को रणनीतिक सहयोग प्रदान करेगी। उपराज्यपाल ने कठिन मौसम और ऊंचाई वाली परिस्थितियों में दिन-रात काम करने वाले इंजीनियरों, कर्मचारियों और श्रमिकों की भी सराहना की।